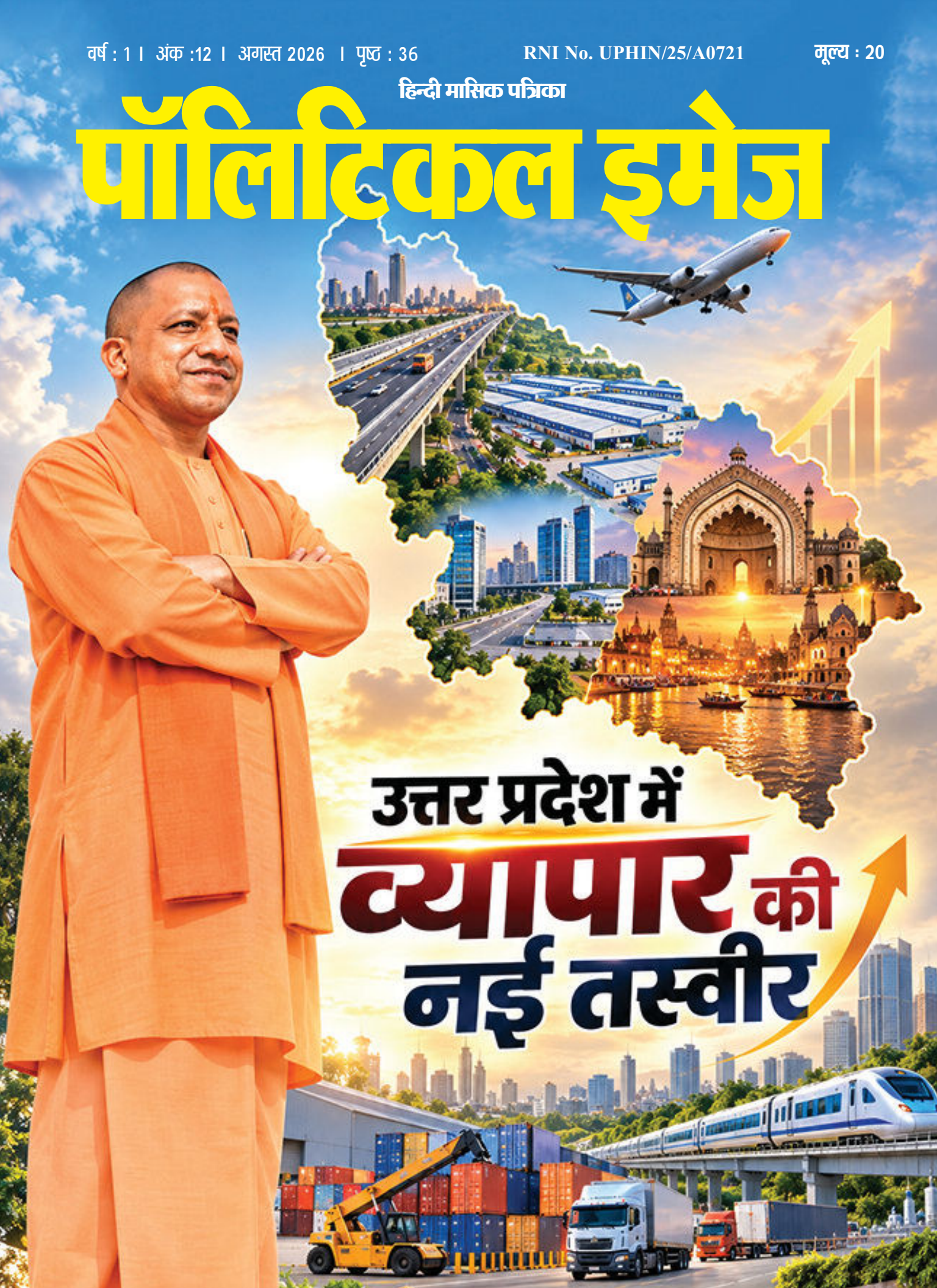
वर्ष : 1 । अंक :12 । अगस्त 2026 । पृष्ठ : 36 RNI No. UPHIN/25/A0721 मूल्य : 20

हिन्दी मासिक पत्रिका

# पॉलिटिकल इमेज



## उत्तर प्रदेश में व्यापार की नई तस्वीर

# जागरूकता ही है बचाव का रास्ता

## सुरक्षित स्कूली वाहन

# पहली प्राथमिकता

**शैक्षणिक सत्र में सुरक्षित स्कूली वाहनों से हो विद्यार्थियों का आवागमन**



### प्रदेश के सभी विद्यालयों के प्रबंधकों से अपील

- स्कूल वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण
- 12 वर्ष तक के विद्यार्थियों के परिवहन में प्रयुक्त स्कूल वाहनों में एक परिचारक/परिचारिका की अनिवार्यता
- वाहन के सुरक्षा मानकों, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी अलार्म आदि उपकरणों की प्रतिमाह हो जांच
- स्कूल वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा एवं अन्य आनुषंगिक प्रपत्रों की वैधता की नियमित जांच तथा अनफिट वाहनों का बहिष्कार



**याद रखिए, छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का पालन तथा अभिभावकों एवं स्कूली प्रबंधन की सजगता अत्यंत आवश्यक है।**

परिवहन हेल्पलाइन
**149 | 1800-1800-151**

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन **1076**

## सुरक्षित बचपन-विकसित उत्तर प्रदेश

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP

# पॉलिटिकल इमेज

वर्ष : 1 । अंक : 12 ।
अगस्त 2026 । पृष्ठ : 36

**संपादक**
गरिमा सिंह

स्वामी, प्रकाशक गरिमा सिंह एवं मुद्रक नीलम श्रीवास्तव द्वारा नीलम प्रिंटिंग प्रेस 41/381 नरही, लखनऊ, ऊ.प्र.-226001 से मुद्रित व सी- 62, इन्दिरा नगर, लखनऊ, ऊ.प्र.-226016 से प्रकाशित।

सम्पादक - गरिमा सिंह

**RNI No. UPHIN/25/A0721**

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।



e-mail
singsgarima@gmail.com

Phone : 8595476939






14 उत्तर प्रदेश में व्यापार...


# इस अंक में




कांवड़ यात्रा : आस्था और... 10





04 तिरंगे की छांव में भारत का...






उत्तर प्रदेश औद्योगिक... 22

# संपादक की कलम से...

## बढ़ता जाए भारत



गरिमा सिंह
सम्पादक

भारत की स्वतंत्रता आज पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। जब भारत की स्वतंत्रता की बात होती है, तब अनायास एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नकारात्मक टिप्पणी की याद आती है। उस प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी एक क्षणिक उद्गार भर साबित होकर रह गई और भारत अपनी आजादी की यात्रा में बहुत आगे निकल आया है। बांटने और बिखेरने की तमाम साजिशों के बावजूद यह देश भारत, जिसे इंडिया के नाम से भी दुनिया जानती है, अपने मुकम्मल वजूद के साथ कायम है। आज इस मुकाम पर ब्रिटेन से अगर हम तुलना करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था उसे कड़ी टक्कर दे रही है। भारत हाल ही में ब्रिटेन से आगे निकल गया था, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के चलते उसकी रफ्तार कुछ घटी है, पर दोनों देश एक-दूसरे को कड़ी प्रतिस्पर्द्धा दे रहे हैं। हम ब्रिटेन के मुकाबले में कोई यूं ही नहीं पहुंच गए हैं। याद कीजिए, जब देश आजाद हुआ था, तब उसकी अर्थव्यवस्था का आकार बमुश्किल 20 अरब डॉलर था, जबकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था उस समय 350 अरब डॉलर के आसपास थी। दोनों देशों के बीच भारी अंतर था, लेकिन अब इस अंतर को भारत ने न केवल पूरी तरह से पाट दिया है, बल्कि ब्रिटिश शासकों की अनेक गलतफहमियों को भी दूर कर दिया है।

बहरहाल, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था हमारा लक्ष्य नहीं है। भारत को अपने आकार-प्रकार के हिसाब से अभी बहुत आगे जाना है। हम आज देख रहे हैं कि हमारा मुकाबला सीधे अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ है। जिस तरह का व्यापारिक तनाव हम इन दोनों महाशक्तियों की ओर से देख रहे हैं, उससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत का वजूद किस तरह से मजबूत हुआ है। अमेरिका आज लगातार आर्थिक तनाव बढ़ा रहा है, लेकिन वह भारत की ताकत को जानता है। ठीक इसी तरह से चीन भी भारत को दबाए रखना या पीछे रखना चाहता है, लेकिन वह भी भारत की ताकत समझता है। भारत की तरक्की का तरीका अमेरिका और चीन की तरक्की के तरीकों से बहुत अलग है। अपने विकास के लिए अमेरिका को अनेक प्रकार के युद्ध से गुजरना पड़ा है, तो चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर कभी करीब 16 लाख लोग मारे गए थे। भारतीयों की स्वाभाविक उदारता का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन यह उदारता कई बार हमारी शिथिलता भी बढ़ा देती है। आजादी के नौवें दशक की ओर बढ़ते देश से सबसे पहले शिथिलता को विदा करना होगा। डिजिटल क्रांति ने देश को सक्रिय किया है, पर अभी जन-जन तक पहुंचने के लिए बहुत ईमानदार प्रयासों की जरूरत है।

आज देश को भटकाने वाले तत्व बहुत हैं। राजनीति का स्तर भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। ऐसे में, एक बार पलटकर इस राष्ट्र की नींव रखने वाले महान निर्माताओं के स्वप्न और संकल्पों पर भी गौर करना चाहिए। राष्ट्र निर्माताओं ने भारत के नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प बार-बार दोहराया था। हमें आज जरूर सोचना चाहिए कि स्वतंत्रता को समानता से ही बल मिलता है। असमानता से समाज में लाचार लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। यह मात्र चुनौती नहीं, एक संकट है, जिसका समाधान मुस्तैदी से करने की जरूरत है। कोई बहुत बड़ा भले हो जाए, पर कोई भी इतना छोटा न होने पाए कि वाजिब हक से भी वंचित हो जाए। यही वह मुकाम है, जब देश की एकता, अखंडता और नवनिर्माण के लिए सभी देशवासियों को संकल्प लेना पड़ेगा।




# योगी सरकार ने गन्ना किसानों को किया रिकार्ड भुगतान

## उत्तर प्रदेश बना देश का सर्वाधिक गन्ना मूल्य भुगतान करने वाला राज्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाया है। प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को 31,682 करोड़ रुपये का भुगतान किया। वहीं वर्ष 2017 से गन्ना किसानों को अब तक 3,23,572 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया है। देश का सर्वाधिक गन्ना मूल्य भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश निरंतर प्रथम स्थान पर बना हुआ है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अनुसार वर्ष 1995 से 2017 तक के 22 वर्ष में किसानों को कुल 2,13,519 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार ने मात्र नौ वर्ष में ही इससे 1,10,053 करोड़ रुपये अधिक भुगतान करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं वर्ष 2007 से 2017 (10 वर्ष) में कुल 1,47,346 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था, जबकि वर्ष 2017 से अब तक 3,23,572 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

### मिलों ने 89.52 लाख टन चीनी का उत्पादन किया

प्रदेश में योगी सरकार की किसान हितैषी नीतियों का असर वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 में भी दिखाई दे रहा है। इस सत्र में अब तक किसानों को 31,682 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल देय राशि का 91.64 प्रतिशत है। गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की हैं। पेराई सत्र 2025-26 में प्रदेश की 121 संचालित चीनी मिलों ने 878.12 लाख टन गन्ने की पेराई कर 89.52 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है।

### 10 लाख लोगों को मिला रोजगार

मार्च 2017 से अब तक प्रदेश में 04 नई चीनी मिलों की स्थापना की गई है, जबकि 07 बंद चीनी मिलों का पुनर्संचालन किया गया है। इसके अलावा 42 निजी क्षेत्र, 01 निगम क्षेत्र और 01 सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में क्षमता विस्तार किया गया है। इन प्रयासों से 1,28,500 टीसीडी अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन हुआ है। नई औद्योगिक इकाइयों और क्षमता विस्तार के परिणामस्वरूप लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश में 2016-17 में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर था, जो नौ वर्षों में 39.29 प्रतिशत बढ़कर 28.61 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसी अवधि में गन्ने की औसत उत्पादकता 72.38 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 83.25 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। उन्नत गन्ना प्रजातियों, वैज्ञानिक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर 10.87 टन की वृद्धि दर्ज की गई है।

### गन्ना किसानों की संख्या में भी बड़ी वृद्धि

गन्ना किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश में लगभग 33 लाख गन्ना किसान थे, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 48 लाख हो गई है यानी नौ वर्ष में 15 लाख किसानों की वृद्धि हुई है। बढ़ते क्षेत्रफल, बेहतर उत्पादकता, रिकॉर्ड भुगतान और किसानों की संख्या में वृद्धि यह दर्शाती है कि प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण गन्ना किसानों की आय में वृद्धि हुई है। इन्हीं उपलब्धियों के बल पर उत्तर प्रदेश आज देश में गन्ना उत्पादन और गन्ना मूल्य भुगतान दोनों क्षेत्रों में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है।

# तिरंगे की छांव में भारत का संकल्प

## उत्तर प्रदेश की नई उड़ान

### लाल किले से प्रधानमंत्री का संदेश : 80 वर्ष की यात्रा से विकसित भारत की ओर




80वें स्वतंत्रता दिवस पर इतिहास की उपलब्धियों के साथ उसके कठिन अध्यायों को याद करना भी जरूरी है। हालांकि इतिहास की राजनीतिक व्याख्या को लेकर अलग-अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि विभाजन की पीड़ा लाखों परिवारों के जीवन से जुड़ी हुई है। उस स्मृति का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी में वैमनस्य पैदा करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करना होना चाहिए।



भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय समारोह केवल अतीत की स्मृतियों का उत्सव नहीं रहा, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला अवसर भी बना। नई दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्वतंत्र भारत की आठ दशक लंबी यात्रा, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार, महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में बढ़ती भूमिका और देश को आगे ले जाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री के संबोधन के आधिकारिक विवरण में विशेष रूप से राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित किया गया।

प्रधानमंत्री का संदेश इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा कि स्वतंत्रता की उपलब्धि को केवल राजनीतिक आजादी के रूप में नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में अवसर, सुरक्षा, सम्मान और विकास के विस्तार के रूप में देखा जाए। सामाजिक सुरक्षा के विस्तार पर भी प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से प्रकाश डाला और बताया कि पिछले दशक में सामाजिक सुरक्षा का दायरा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

यह संदेश उस भारत की तस्वीर सामने रखता है जो स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ पर अपने अतीत का सम्मान करते हुए 2047 की ओर देख रहा है। आजादी की शताब्दी तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास का विषय नहीं है। इसमें सामाजिक समावेशन, महिला शक्ति, युवाओं की भागीदारी, तकनीकी आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार भी शामिल हैं।

यही कारण है कि 2026 का स्वतंत्रता दिवस एक महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ता है—आजादी के 80 वर्षों की उपलब्धियों को अगले 21 वर्षों में विकसित भारत की शक्ति में कैसे बदला जाए?

## उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राष्ट्र और विकास का संदेश

उत्तर प्रदेश में 80वें स्वतंत्रता दिवस का केंद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन और प्रदेशवासियों से किया गया आह्वान रहा। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों से राष्ट्र की मजबूती के लिए सामूहिक प्रयास करने और देश को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की।

योगी आदित्यनाथ का संदेश ऐसे समय आया जब उत्तर प्रदेश स्वयं विकास और परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री के संबोधन में राष्ट्रभक्ति को केवल भावनात्मक विषय न मानकर उसे राष्ट्र निर्माण और विकास के साथ जोड़ने का प्रयास दिखाई दिया।

उनका जोर इस बात पर रहा कि भारत की शक्ति उसकी एकता में है। ऐसे समय में जब समाज और राजनीति में विभिन्न प्रकार के मतभेद दिखाई देते हैं, राष्ट्रीय एकता और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष महत्व रखता है।

## योगी के संबोधन में इतिहास और वर्तमान राजनीति का संदर्भ

स्वतंत्रता दिवस से पहले और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के विभाजन और उसके परिणामों का भी उल्लेख किया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के



संदर्भ में उन्होंने विभाजन की त्रासदी को इतिहास का अत्यंत पीड़ादायक अध्याय बताया और तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व के निर्णयों पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने यह भी कहा कि यदि 1947 में सरदार पटेल अथवा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व होता तो इतिहास की दिशा अलग हो सकती थी। 15 अगस्त के अवसर पर भी योगी आदित्यनाथ ने विभाजन को लेकर अपनी राजनीतिक-ऐतिहासिक व्याख्या रखी और इसे देश के इतिहास की गंभीर त्रासदी के रूप में प्रस्तुत किया। इन टिप्पणियों को केवल राजनीतिक बयान के रूप में देखने के बजाय स्वतंत्रता दिवस के व्यापक विमर्श में भी देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के साथ भारत को विभाजन, विस्थापन और हिंसा का दर्द भी मिला था। इसलिए 80वें स्वतंत्रता दिवस पर इतिहास की उपलब्धियों के साथ उसके कठिन अध्यायों को याद करना भी जरूरी है। हालांकि इतिहास की राजनीतिक व्याख्या को लेकर अलग-अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि विभाजन की पीड़ा लाखों परिवारों के जीवन से जुड़ी हुई है। उस स्मृति का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी में वैमनस्य पैदा करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करना होना चाहिए।

## मुख्यमंत्री का विकास मॉडल और स्वतंत्रता का आधुनिक अर्थ

योगी आदित्यनाथ के स्वतंत्रता दिवस संदेश को उत्तर प्रदेश की वर्तमान विकास यात्रा से जोड़कर देखें तो इसमें राष्ट्रवाद के साथ विकास और आत्मनिर्भरता का पक्ष भी दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, औद्योगिक निवेश, धार्मिक पर्यटन, बुनियादी ढांचे, एयर कनेक्टिविटी, डिजिटल सेवाओं और रोजगार के नए अवसरों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता का आधुनिक अर्थ केवल यह नहीं है कि देश स्वयं अपने निर्णय ले। इसका अर्थ यह भी है कि देश अपनी अर्थव्यवस्था, तकनीक, ऊर्जा, रक्षा, शिक्षा और मानव संसाधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। यही विचार उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल में भी दिखाई देता है—बड़े निवेश के साथ छोटे उद्यमी, आधुनिक उद्योग के साथ स्थानीय कारीगर, धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय रोजगार और बुनियादी ढांचे के साथ गांवों की कनेक्टिविटी।

## प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय संबोधन और मुख्यमंत्री के संबोधनों का केंद्रीय वृत्त : युवा

प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय संबोधन और मुख्यमंत्री के प्रदेशीय संदेश को एक साथ देखने पर एक महत्वपूर्ण विषय सामने आता है - युवा भारत। भारत की वर्तमान जनसांख्यिकीय शक्ति को 2047 के भारत की सबसे बड़ी पूंजी माना जा सकता है। आज का युवा ही आने वाले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था, प्रशासन, विज्ञान, तकनीक, उद्योग, राजनीति और सामाजिक जीवन का नेतृत्व करेगा। इसलिए स्वतंत्रता दिवस का संदेश केवल अतीत के बलिदानों की स्मृति तक सीमित नहीं रह सकता। युवाओं को रोजगार, उद्यमिता, कौशल, शिक्षा, तकनीक और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के अवसर देना भी स्वतंत्रता के आधुनिक अर्थ का हिस्सा है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से संबंधित पहल को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य युवाओं को व्यवसाय और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना है। यह पहल इस बात की ओर संकेत करती है कि आजादी की अगली मंजिल केवल नौकरी तलाशने वाला युवा भारत नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला और उद्यम खड़ा



करने वाला युवा भारत होना चाहिए।

## 'हर घर तिरंगा' सरकार से समाज तक

उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का एक बड़ा केंद्र 'हर घर तिरंगा' अभियान रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में करोड़ों घरों तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने और स्वतंत्रता दिवस को जनभागीदारी का पर्व बनाने पर जोर दिया। यह पहल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राष्ट्रभक्ति को सरकारी कार्यक्रमों की सीमा से निकालकर सामान्य नागरिक के घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। गांव की पंचायत से लेकर शहर की कॉलोनी तक, स्कूल से लेकर बाजार तक और सरकारी कार्यालय से लेकर निजी प्रतिष्ठानों तक तिरंगे की उपस्थिति ने स्वतंत्रता दिवस को व्यापक सामाजिक उत्सव का रूप दिया।

## उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव

उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के प्रत्येक जिले और गांव तक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सरकारी भवनों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और सामाजिक संस्थाओं में ध्वजारोहण हुआ।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालयों में बच्चों ने देशभक्ति गीत, भाषण, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विभिन्न जिलों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम हुए।

गांवों में भी तिरंगे के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा को व्यापक बनाने पर जोर रहा। अमृत सरोवरों, ग्राम सचिवालयों और पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे।

इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत की लोकतांत्रिक शक्ति केवल महानगरों में नहीं, बल्कि गांवों की भागीदारी में भी निहित है।

## स्वतंत्रता के 80 वर्ष

80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय संदेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के नाम संदेश मिलकर एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

एक ओर देश की आठ दशक की यात्रा है-गरीबी से लड़ाई, लोकतंत्र की मजबूती, विज्ञान और तकनीक में प्रगति, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका।

दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की यात्रा है-कानून-व्यवस्था, आधारभूत ढांचे, धार्मिक पर्यटन, निवेश, उद्योग, एक्सप्रेसवे, हवाई संपर्क, डिजिटल प्रशासन और युवाओं के लिए नए अवसरों की दिशा में प्रयास।

लेकिन उपलब्धियों के साथ चुनौतियां भी हैं। रोजगार, शिक्षा की गुणवत्ता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक संवाद जैसे प्रश्न अभी भी हमारे सामने हैं।

स्वतंत्रता दिवस इन प्रश्नों से बचने का नहीं, बल्कि उनका सामना करने का अवसर है।

## 2047 की ओर : प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संदेशों का साझा सूत्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए संदेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में दिए गए संदेशों का एक साझा सूत्र है—राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सामूहिक भागीदारी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लोगों से राष्ट्र की मजबूती के लिए योगदान देने और देश को कमजोर करने वाली शक्तियों से सावधान रहने की अपील की।

इन दोनों संदेशों को 2047 की दृष्टि से देखें तो स्पष्ट होता है कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल सरकारों के प्रयास से पूरा नहीं होगा। इसके लिए किसान, मजदूर, व्यापारी, वैज्ञानिक, शिक्षक, सैनिक, महिला, युवा, उद्यमी और सामान्य नागरिक—सभी की भागीदारी आवश्यक होगी।

## तिरंगे से 2047 तक

भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस इतिहास और भविष्य के बीच खड़े एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह है। लाल किले से प्रधानमंत्री का संदेश राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विकास यात्रा और सामाजिक परिवर्तन की दिशा प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश राष्ट्र की एकता, सामूहिक जिम्मेदारी, विकास और युवा शक्ति को केंद्र में रखता है।

आजादी के 80 वर्ष बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि हमने क्या हासिल किया। उससे बड़ा प्रश्न यह है कि अगले 21 वर्षों में हम क्या हासिल करना चाहते हैं। 2047 में जब भारत स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब आज का युवा उस भारत का नागरिक होगा। इसलिए 2026 का स्वतंत्रता दिवस केवल स्मरण का दिन नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण का संकल्प है। तिरंगा केवल आसमान में लहराता हुआ राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। वह हमारी स्वतंत्रता, संप्रभुता, त्याग, संघर्ष और भविष्य की आकांक्षा का प्रतीक है।

1947 ने भारत को स्वतंत्र बनाया।

2026 हमें उसकी 80 वर्ष की यात्रा का मूल्यांकन करने का अवसर देता है।

और 2047 हमें यह बताने का अवसर देगा कि हमने उस स्वतंत्रता से कैसा भारत बनाया।

यही 80वें स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा संदेश है इतिहास पर गर्व, वर्तमान का मूल्यांकन और 2047 के भारत के निर्माण का संकल्प।




तिरंगा यात्रा
योगी आदित्यनाथ जी महाराज का
हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन
नगर निगम गोरखपुर
तिरंगा
LG
BEST SHOP
CAMPUS
Bata
GLETA



# कांवड़ यात्रा : आस्था और परंपरा का संगम

**कांवड़ यात्रा केवल एक पैदल यात्रा नहीं है, अपितु यह कठोर तपस्या, मानसिक संयम एवं शारीरिक शक्ति की परीक्षा है। कांवड़ मुख्य रूप से बांस की फच्चियों से बनाई जाती है।**

हिंदू धर्म में श्रावण का मास केवल ऋतु परिवर्तन का सूचक नहीं है, अपितु यह अगाध श्रद्धा, भक्ति एवं आध्यात्मिक चेतना का मास माना जाता है। श्रावण का मास महादेव को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र मास के प्रारंभ होते ही संपूर्ण देश विशेष रूप से उत्तर एवं मध्य भारत भक्तिमय वातावरण में लीन हो जाता है। इस भक्ति पर्व का सबसे जीवंत, भव्य एवं कठिन रूप 'कांवड़ यात्रा' के रूप में दिखाई देता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने कंधों पर कांवड़ तथा उसमें पवित्र नदियों का जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल पड़ते हैं।

## पौराणिक महत्व

पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा का प्रारंभ समुद्र मंथन के समय हुए 'विषपान' की घटना से संबंधित है। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से महादेव का शरीर अत्यधिक उष्ण हो गया और उनका कंठ नीला पड़ गया, जिससे वे 'नीलकंठ' कहलाए। विष के नकारात्मक प्रभाव एवं जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का शीतल जल अर्पित किया था। इससे उन्हें शांति प्राप्त हुई। तभी से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई।

एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्रीराम को पहला कांवड़िया माना जाता है। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर के वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार लंका नरेश रावण ने हरिद्वार से जल लाकर पुरा महादेव में शिवशंकर को अर्पित किया था। यह परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है।

## कांवड़ यात्रा

कांवड़ यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं को 'कांवड़िया' कहा जाता है। यह यात्रा मुख्य रूप से गंगा नदी के तटों से प्रारंभ होती है तथा विभिन्न प्रमुख ज्योतिर्लिंगों अथवा प्रसिद्ध शिव मंदिरों पर जाकर समाप्त होती है। इसके प्रमुख प्रस्थान केंद्रों में उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, गौमुख तथा उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर, ब्रजघाट, सोरो तथा बिहार में सुल्तानगंज आदि सम्मिलित हैं।

हरिद्वार से जल भरने वाले कांवड़िए विभिन्न शिव मंदिरों जैसे नीलकंठ महादेव, पुरा महादेव, काशी विश्वनाथ एवं अपने-अपने गृह नगरों के स्थानीय शिव मंदिरों में जल अर्पित करने जाते हैं। बिहार के सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल



लेकर निकलने वाले श्रद्धालु कठिन पैदल यात्रा करके झारखंड के देवघर स्थित 'बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग' पर जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा केवल एक पैदल यात्रा नहीं है, अपितु यह कठोर तपस्या, मानसिक संयम एवं शारीरिक शक्ति की परीक्षा है। कांवड़ मुख्य रूप से बांस की फच्चियों से बनाई जाती है, जिसके दोनों सिरों पर टोकरियां या बर्तन बांधकर उनमें गंगाजल के कलश रखे जाते हैं। कांवड़ यात्रा के कई रूप देखने को मिलते हैं। सामान्य कांवड़ में कांवड़िया पैदल चलते हैं तथा मार्ग में विश्राम शिविरों में रुकते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। डाक कांवड़ यात्रा का सबसे कठिन रूप है। इसमें श्रद्धालुओं का एक समूह बिना रुके, निरंतर दौड़ते हुए जल अर्पित करने जाता है। जल भरने के पश्चात से लेकर शिवलिंग पर अर्पित करने तक कांवड़ को एक क्षण के लिए भी भूमि पर नहीं रखा जाता। खड़ी कांवड़ में यात्रा में कांवड़ को कभी भी भूमि या किसी स्टैंड पर नहीं रखा जाता। यदि कांवड़िया विश्राम करता है, तो उसका सहयोगी कांवड़ को अपने कंधे पर साधे रखता है। झांकी कांवड़ में बड़े-बड़े ट्रकों एवं ट्रॉलियों पर भगवान शिव की विशाल मूर्तियां और झांकियां सजाकर यात्रा निकाली जाती है। आजकल इसका चलन बहुत बढ़ गया है।

कांवड़ यात्रा के समय कांवड़िए अत्यंत कठोर नियमों का पालन करते हैं। संपूर्ण यात्रा में सात्विक आहार, स्वच्छता, ब्रह्मचर्य एवं मन-वचन-कर्म से पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य होता है। मार्ग में एक-दूसरे को 'बम' या 'शिवभक्त' कहकर संबोधित किया जाता है, जिससे जात-पात एवं ऊंच-नीच का भेदभाव समाप्त हो जाता है।

## गाजे-बाजे पर नृत्य

श्रावण के मास में सड़कें 'बम-बम भोले' एवं 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठती हैं। कांवड़ियों के जत्थे गाजे-बाजे एवं डीजे पर बजते शिव भजनों एवं धार्मिक धुनों पर नाचते-गाते हुए आगे बढ़ते हैं। सड़कों पर केवल कांवड़िए ही कांवड़िए दिखाई देते हैं।

## विशेष प्रबंध

सरकार एवं प्रशासन कांवड़ियों के लिए विशेष प्रबंध करते हैं। विद्यालय



बंद कर दिए जाते हैं। पुलिस प्रशासन भी सब कार्य छोड़कर कांवड़ियों की सेवा में लग जाता है। इन पर पुष्प वर्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं एवं स्थानीय निवासियों द्वारा भी कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन, स्वच्छ पेयजल, विश्राम स्थल एवं चिकित्सा सेवाएं विशेष रूप से पैरों के छालों एवं मालिश की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है।

## यातायात व जनजीवन पर प्रभाव

कांवड़ यात्रा प्रशासन एवं पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। श्रावण के मास में लाखों लोग सड़कों पर होते हैं। लाखों की पैदल भीड़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे दिल्ली-हरिद्वार एनएच-58 एवं राज्य मार्गों पर सामान्य यातायात को रोकना या परिवर्तित करना पड़ता है। भारी वाहनों एवं बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

रूट परिवर्तित करने से मुख्य मार्गों पर कई-कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगना सामान्य बात हो जाती है। इससे दैनिक यात्रियों, कार्यालय जाने वालों, स्कूली बच्चों एवं आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों एवं ड्रोन कैमरों की तैनाती की जाती है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जाती है तथा कांवड़ियों के लिए सड़कों का एक भाग पूर्ण रूप से आरक्षित कर दिया जाता है। यात्रा के पश्चात मार्गों एवं गंगा घाटों पर प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथिन एवं कचरे का विशाल ढेर लग जाता है। नदियों की स्वच्छता एवं पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। कांवड़ यात्रा भारतीय संस्कृति की उस महान धारा का प्रतीक है जिसमें श्रद्धा, संकल्प, शारीरिक क्षमता एवंसामाजिक समरसता का संगम होता है। यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का मार्ग नहीं है, अपितु यह अहंकार को त्याग कर शिवत्व में लीन होने की एक आध्यात्मिक साधना है। यदि इस पावन यात्रा को पूर्ण अनुशासन, पर्यावरण-सचेत व्यवहार एवं नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए संपन्न किया जाए, तो यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अपितु एक अनुशासित एवं सुसंगठित समाज के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होगी।



# उत्तर प्रदेश में व्यापार की नई तस्वीर

## ग्लोबल मंच पर बढ़ती कारोबारी ताकत

उत्तर प्रदेश लंबे समय तक अपनी विशाल आबादी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और पारंपरिक कारोबार के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश की आर्थिक और कारोबारी तस्वीर तेजी से बदली है। कानून-व्यवस्था में सुधार, बेहतर कनेक्टिविटी, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण और कारोबार को सरल बनाने वाली नीतियों ने उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख कारोबारी एवं निवेश केंद्रों की कतार में ला खड़ा किया है।

अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल का मानना है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश के व्यापार, उद्योग और निर्यात को



नई गति देने वाला महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। उनके अनुसार, इस तरह के आयोजनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है।

## इंटरनेशनल ट्रेड शो से वैश्विक बाजार तक पहुंच

नोएडा में आयोजित होने वाला उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश के कारोबारी सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह आयोजन केवल व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैयार होने वाले उत्पादों, हस्तशिल्प, पारंपरिक उद्योगों, एमएसएमई इकाइयों और आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक बाजार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

संदीप बंसल के अनुसार, उत्तर प्रदेश में प्रतिभा और उत्पादों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों की अपनी विशिष्ट पहचान और उत्पाद हैं। जरूरत इस बात की है कि इन उत्पादों को बेहतर ब्रांडिंग, आधुनिक पैकेजिंग, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जाए। इंटरनेशनल ट्रेड शो इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के उत्पादों को वैश्विक मंच उपलब्ध कराने की कोशिश का असर आने वाले वर्षों में प्रदेश के निर्यात और स्थानीय रोजगार पर भी दिखाई दे सकता है। यदि किसी छोटे शहर या ग्रामीण क्षेत्र में तैयार होने वाला उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है तो इसका सीधा लाभ उस उत्पाद से जुड़े कारीगर, व्यापारी, उद्यमी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलता है।

## बदली कानून-व्यवस्था ने बनाया व्यापार का माहौल

किसी भी राज्य में व्यापार और निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में कानून-व्यवस्था का स्थान सबसे ऊपर होता है। व्यापारियों और निवेशकों को ऐसा वातावरण चाहिए जहां उनकी संपत्ति, कारोबार और निवेश सुरक्षित रहे तथा उन्हें अनावश्यक दबाव या असुरक्षा का सामना न करना पड़े।

संदीप बंसल का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। उनके अनुसार, प्रदेश में कानून का राज मजबूत हुआ है और इसका सकारात्मक प्रभाव कारोबारी वातावरण पर पड़ा है।

व्यापारियों के दृष्टिकोण से देखें तो कानून-व्यवस्था में सुधार केवल अपराध नियंत्रण का विषय नहीं है। यह सीधे तौर पर बाजार के भरोसे, निवेश के फैसले, कारोबार के विस्तार और रोजगार सृजन से जुड़ा हुआ है। जब किसी व्यापारी को अपने कारोबार की



सुरक्षा का भरोसा होता है तो वह अपने व्यवसाय में अधिक निवेश करने और उसे विस्तार देने के लिए तैयार होता है।

यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रति बढ़ती रुचि को कानून-व्यवस्था में सुधार से जोड़कर देखा जा रहा है।

## वन विंडो व्यवस्था से कारोबार को सरल बनाने की कोशिश

व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केवल कानून-व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। निवेशकों और उद्यमियों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाना भी उतना ही आवश्यक है। लंबे समय तक विभिन्न विभागों की अनुमति, कागजी प्रक्रिया और प्रशासनिक औपचारिकताएं कारोबार शुरू करने में बड़ी चुनौती मानी जाती थीं।

उत्तर प्रदेश में वन विंडो व्यवस्था के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न स्वीकृतियां और अनुमतियां एकीकृत प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाना है।

संदीप बंसल के मुताबिक, व्यापार को सरल बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई स्तरों पर काम हुआ है। व्यापारियों के लिए सुविधाएं बढ़ाना, निवेश प्रक्रिया को आसान करना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना इस बदलाव का हिस्सा है।

कारोबार की दृष्टि से देखें तो किसी निवेशक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसे जमीन, बिजली, पानी, अनुमति, परिवहन और अन्य सुविधाओं के लिए स्पष्ट व्यवस्था मिले। जब इन प्रक्रियाओं में अनिश्चितता कम होती है तो निवेश के निर्णय लेने में भी आसानी होती है।

## कनेक्टिविटी बनी उत्तर प्रदेश की बड़ी ताकत

उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उसे देश के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में शामिल करती है। लेकिन केवल भौगोलिक स्थिति किसी राज्य को व्यापारिक ताकत नहीं बना सकती। इसके लिए मजबूत सड़क, रेल और हवाई संपर्क आवश्यक है।

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और अन्य आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा लाभ व्यापार और उद्योग को मिलता है। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचाना, उत्पादन केंद्रों को बाजार से जोड़ना और निर्यात के लिए लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराना कारोबारी प्रतिस्पर्धा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

संदीप बंसल के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सड़क और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हुए काम ने व्यापार के लिए नई संभावनाएं पैदा की हैं। जब प्रदेश के अलग-अलग हिस्से बेहतर परिवहन नेटवर्क से जुड़ते हैं तो छोटे शहरों और जिलों के कारोबारी भी बड़े बाजार तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

## कच्चे माल से लेकर बाजार तक पूरी श्रृंखला मजबूत करने की जरूरत

किसी भी उद्योग की सफलता केवल फैक्ट्री लगाने से सुनिश्चित नहीं होती। उसके लिए कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल श्रम, बिजली, परिवहन, तकनीक, वित्त और बाजार की आवश्यकता होती है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की बड़ी भूमिका है। ऐसे में कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय उद्योगों को आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की काफी संभावनाएं हैं।

स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रमाणन पर भी ध्यान देना होगा। इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे आयोजन इस पूरी प्रक्रिया में एक कड़ी का काम कर सकते हैं।

यदि किसी जिले का पारंपरिक उत्पाद अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचता है और उसे बड़े ऑर्डर मिलते हैं तो उसका प्रभाव केवल एक कारोबारी तक सीमित नहीं रहता। इससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और छोटे उद्यमियों की आय में वृद्धि होती है।

## 'व्यापारी दिवस' की पहल और व्यापारी समाज की भूमिका

उत्तर प्रदेश में व्यापारी दिवस घोषित किया जाना भी व्यापारी समाज के लिए महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। 3 सितंबर



को व्यापारी दिवस के रूप में मनाने की पहल व्यापारियों के योगदान को औपचारिक पहचान देने की दिशा में एक कदम है।

व्यापारी केवल वस्तुओं की खरीद-बिक्री करने वाला वर्ग नहीं है। वह उत्पादन और उपभोक्ता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। देश की अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम व्यापारियों की भूमिका रोजगार, कर संग्रह, वितरण व्यवस्था और स्थानीय बाजारों के संचालन में महत्वपूर्ण है।

संदीप बंसल का कहना है कि व्यापारी दिवस की अवधारणा को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि व्यापारियों की आर्थिक भूमिका के साथ-साथ उनके सामाजिक योगदान को भी पहचान मिलनी चाहिए।

वास्तव में देश के छोटे शहरों और कस्बों की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय बाजारों में रोजगार पैदा करने से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुएं पहुंचाने तक व्यापारी आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख वाहक हैं।

## निवेश के साथ रोजगार पर भी नजर

उत्तर प्रदेश में बढ़ते निवेश की चर्चा के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल रोजगार का है। बड़े निवेश से तभी व्यापक आर्थिक लाभ मिलेगा जब उसके साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बढ़ें।

नई फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों के साथ सप्लाई चेन, परिवहन, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, सर्विस सेक्टर और छोटे उद्योगों के लिए भी अवसर पैदा होते हैं। यही कारण है कि बड़े निवेश को स्थानीय एमएसएमई और छोटे व्यापारियों से जोड़ना जरूरी है।

उत्तर प्रदेश के लिए चुनौती और अवसर दोनों यही हैं कि बड़े उद्योगों के साथ छोटे कारोबारियों और स्थानीय उद्यमियों को भी विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाए।

## स्थानीय से वैश्विक बनने की दिशा में उत्तर प्रदेश




उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ा अवसर यह है कि वह अपने स्थानीय उत्पादों को वैश्विक ब्रांड में बदल सकता है। प्रदेश के पास पारंपरिक हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल, खाद्य उत्पाद, चमड़ा, कालीन, पीतल, कांच, लकड़ी के उत्पाद और अनेक स्थानीय उद्योगों की समृद्ध विरासत है।

यदि इन उत्पादों को आधुनिक डिजाइन, तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग और अंतरराष्ट्रीय मानकों से जोड़ा जाए तो इनके लिए दुनिया के बड़े बाजारों में जगह बनाना संभव है।

इंटरनेशनल ट्रेड शो इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला मंच है। यहां स्थानीय उद्यमी सीधे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से संपर्क कर सकते हैं। इससे उन्हें बाजार की जरूरत समझने, नए कारोबारी रिश्ते बनाने और अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है।

## आगे की राहः कारोबार को और आसान बनाना होगा

उत्तर प्रदेश ने व्यापार और निवेश के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन आगे की यात्रा और बड़ी है। प्रदेश को वैश्विक कारोबारी केंद्र बनाने के लिए नीतियों की निरंतरता, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में और अधिक सरलता, एमएसएमई को वित्तीय सहायता, कौशल विकास, डिजिटल तकनीक और निर्यात क्षमता बढ़ाने पर लगातार काम करना होगा।

व्यापारियों के लिए यह भी जरूरी है कि सरकार और कारोबारी संगठनों के बीच नियमित संवाद बना रहे। व्यापारियों की जमीनी समस्याओं को नीति निर्माण तक पहुंचाने और समाधान की प्रक्रिया को तेज करने में व्यापारिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

उत्तर प्रदेश की बदलती कारोबारी तस्वीर यह संकेत देती है कि प्रदेश अब केवल एक बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं रहना चाहता, बल्कि उत्पादन, निवेश और निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था, कनेक्टिविटी, निवेश सुविधाओं, औद्योगिक विकास और व्यापार को सरल बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों ने कारोबारी वातावरण को नई पहचान दी है। इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे आयोजन इस बदलाव को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का माध्यम बन रहे हैं।

# आस्था से अर्थव्यवस्था तक

## उत्तर प्रदेश पर्यटन ने लिखी विकास की नई कहानी

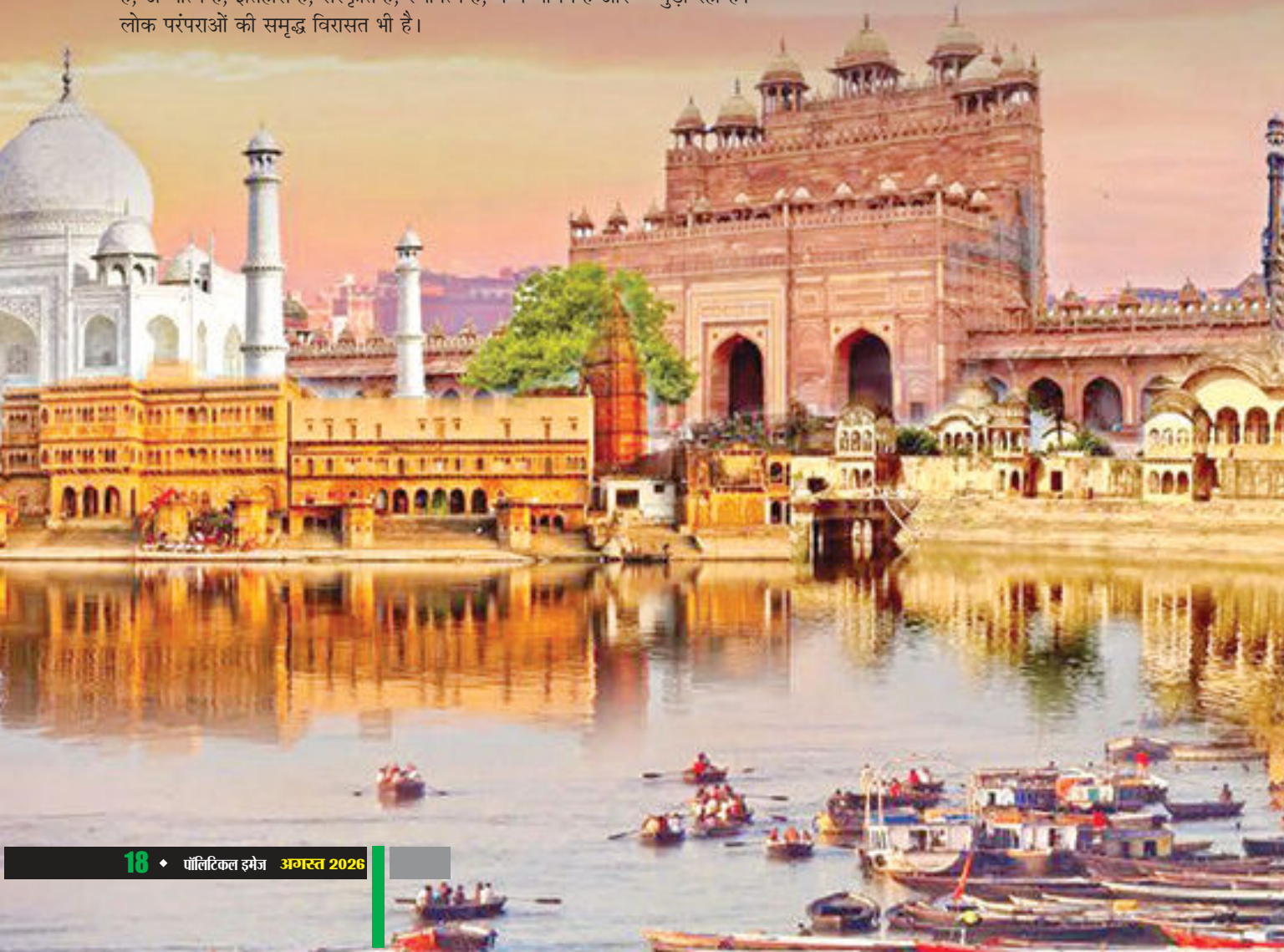
### योगी सरकार में आध्यात्मिक विरासत से वैश्विक पहचान तक-अयोध्या, काशी मथुरा से लेकर बौद्ध सर्किट और वन्य पर्यटन तक बदल रही प्रदेश की तस्वीर

भारत की सांस्कृतिक आत्मा यदि किसी प्रदेश में सबसे अधिक सजीव दिखाई देती है, तो वह उत्तर प्रदेश है। भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान श्रीकृष्ण की लीलाभूमि मथुरा-वृंदावन, भगवान शिव की अनादि नगरी काशी, भगवान बुद्ध की ज्ञान और उपदेश परंपरा से जुड़ी सारनाथ और कुशीनगर की भूमि, जैन तीर्थों की गौरवशाली विरासत और विश्वविख्यात ताजमहल—ये सभी उत्तर प्रदेश को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं।

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता है। यहां धर्म है, अध्यात्म है, इतिहास है, संस्कृति है, स्थापत्य है, वन्य जीवन है और लोक परंपराओं की समृद्ध विरासत भी है।

हालांकि लंबे समय तक इतनी विशाल पर्यटन संभावनाओं के बावजूद प्रदेश का पर्यटन क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया था। पिछले कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन को केवल धार्मिक यात्रा तक सीमित रखने के बजाय इसे विकास, रोजगार, सांस्कृतिक संरक्षण और वैश्विक पहचान से जोड़ने की दिशा में प्रयास किया है।

योगी सरकार के दौर में पर्यटन को एक समग्र आर्थिक गतिविधि के रूप में देखने की सोच मजबूत हुई है। धार्मिक पर्यटन के साथ हेरिटेज, आध्यात्मिक, इको-टूरिज्म, ग्रामीण और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन शहरों में दिखाई देता है, जिनकी पहचान सदियों से आस्था और संस्कृति से जुड़ी रही है।



## अयोध्या से काशी तक—आस्था के केंद्रों का कायाकल्प

अगर उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास में सबसे बड़े बदलाव की बात की जाए तो अयोध्या सबसे प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने आती है।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या में बड़े पैमाने पर आधारभूत सुविधाओं का विकास हुआ है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, हवाई संपर्क, घाट, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था और पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विस्तार ने अयोध्या को एक बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का आधार तैयार किया है। अयोध्या में बढ़ती पर्यटक और श्रद्धालु गतिविधियों का असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देता है। होटल, रेस्तरां, परिवहन, फूल-माला, प्रसाद, हस्तशिल्प और स्थानीय कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं।

काशी में भी विकास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना ने मंदिर परिसर को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा है। गंगा घाटों का संरक्षण, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और देव दीपावली जैसे आयोजनों ने वाराणसी की पर्यटन पहचान को और मजबूत किया है। आज काशी केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है। वह भारतीय संस्कृति, दर्शन, संगीत, अध्यात्म और सनातन परंपरा का वैश्विक प्रतीक बनकर उभर रही है। इसी प्रकार मथुरा-वृंदावन और बरसाना में ब्रज संस्कृति को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में काम हुआ है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि, बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा और बरसाना जैसे धार्मिक स्थलों के आसपास सुविधाओं के विकास से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यात्रा अधिक सुगम बनाने का प्रयास किया गया है।

ब्रज की होली, जन्माष्टमी और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों को बड़े स्तर पर प्रस्तुत किए जाने से ब्रज की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार मिला है।

## बुद्ध की धरती से दुनिया तक

उत्तर प्रदेश की पर्यटन विरासत केवल हिंदू धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है। प्रदेश बौद्ध धर्म की विश्वव्यापी विरासत का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। सारनाथ वह पवित्र भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया। वहीं कुशीनगर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से जुड़ा प्रमुख स्थल है। श्रावस्ती, संकिसा और कौशांबी भी बौद्ध परंपरा में विशेष महत्व रखते हैं। योगी सरकार ने बौद्ध सर्किट के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। इन स्थलों पर सड़क, पर्यटन सुविधाओं और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन से अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश की यात्रा को नई सुविधा मिली है। दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य देशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बौद्ध सर्किट को जोड़ने की संभावनाएं बढ़ी हैं। यह पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत की बौद्ध विरासत को दुनिया के उन देशों से जोड़ने में उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां बौद्ध धर्म की बड़ी आबादी और गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं। इसके अलावा चित्रकूट, विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। इन क्षेत्रों का संतुलित विकास स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है।



## पर्यटन से रोजगार तक-ODOP और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत

पर्यटन केवल किसी स्थान को देखने और वापस लौटने का नाम नहीं है। इसके साथ होटल, परिवहन, रेस्तरां, गाइड, फूल-माला, प्रसाद, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद, टैक्सी, ई-रिक्शा और अनेक छोटे कारोबार सीधे जुड़े होते हैं। यही कारण है कि पर्यटन को रोजगार का बड़ा माध्यम माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए 'एक जिला, एक उत्पाद' (ODOP) जैसी पहल को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों की विशिष्ट कला, शिल्प और उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। जब कोई पर्यटक किसी शहर में जाता है और वहां के स्थानीय हस्तशिल्प, वस्त्र, सजावटी सामान या पारंपरिक उत्पाद खरीदता है, तो पर्यटन का लाभ सीधे स्थानीय कारीगर तक पहुंचता है।

इस तरह पर्यटन और स्थानीय उद्योग एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं। प्रदेश में दीपोत्सव, देव दीपावली, रंगोत्सव, गंगा महोत्सव, आम महोत्सव जैसे आयोजन भी पर्यटन कैलेंडर को समृद्ध कर रहे हैं। ये आयोजन केवल धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि स्थानीय व्यापार और रोजगार के लिए भी बड़े अवसर पैदा करते हैं। पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें बड़े उद्योगों के साथ छोटे कारोबारी और सामान्य परिवार भी भागीदार बन सकते हैं।

## एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और सुरक्षा—पर्यटन को मिली आधुनिक रफ्तार

पर्यटन की सफलता केवल किसी ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल की प्रसिद्धि पर निर्भर नहीं करती। उसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाएं भी उतनी ही जरूरी हैं।

उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में एक्सप्रेसवे और सड़क नेटवर्क के विस्तार ने पर्यटन स्थलों तक पहुंच को आसान बनाने में योगदान दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसे मार्गों ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी दी है। हवाई संपर्क के विस्तार ने भी पर्यटन को नई गति दी है। अयोध्या और कुशीनगर जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से देश-विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए यात्रा के विकल्प बढ़े हैं। सुरक्षा भी पर्यटन का महत्वपूर्ण आधार है। विशेष रूप से महिला पर्यटकों के लिए सुरक्षित वातावरण पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। पुलिस की सक्रियता, निगरानी व्यवस्था और सार्वजनिक स्थलों पर बेहतर प्रबंधन से पर्यटकों का भरोसा बढ़ता है।

हालांकि आगे की राह में कई चुनौतियां भी हैं। पर्यटकों के लिए बहुभाषी सूचना व्यवस्था, प्रशिक्षित गाइड, बेहतर डिजिटल सुविधाएं, स्वच्छता की निरंतरता और छोटे पर्यटन स्थलों का संतुलित विकास आवश्यक होगा।

इसके साथ ही पर्यटन विकास में पर्यावरण और विरासत संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। अयोध्या, काशी, मथुरा या किसी भी ऐतिहासिक स्थल का विकास उसकी मूल सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए होना चाहिए।

## विरासत की शक्ति से विकास की नई उड़ान

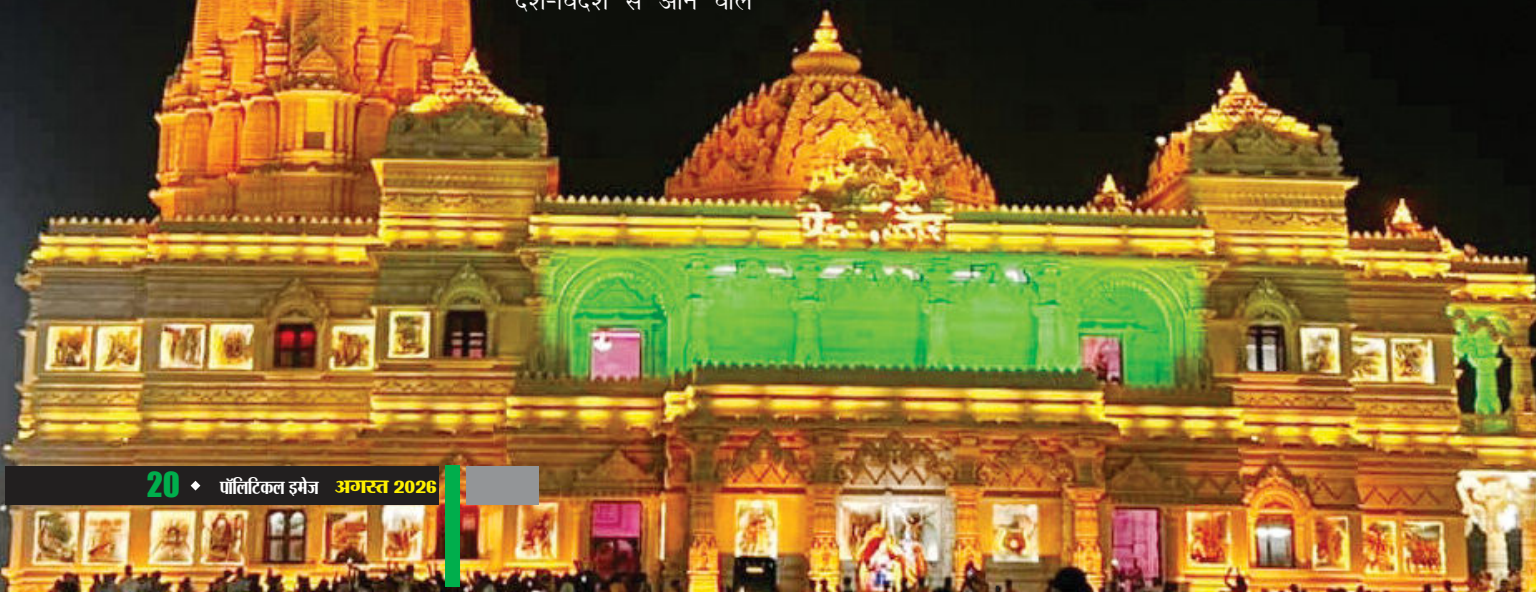
उत्तर प्रदेश का पर्यटन आज एक नए दौर में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। अयोध्या की आध्यात्मिक आभा, काशी की सनातन संस्कृति, ब्रज की कृष्ण भक्ति, सारनाथ और कुशीनगर की बौद्ध विरासत, ताजमहल की विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य कला और बुंदेलखंड-विंध्य की ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक संपदा—प्रदेश के पास पर्यटन की असाधारण विविधता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने पर्यटन को केवल धार्मिक यात्राओं तक सीमित रखने के बजाय उसे रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक संरक्षण और वैश्विक ब्रांडिंग से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

आज उत्तर प्रदेश की चुनौती यह नहीं है कि उसके पास पर्यटन स्थल कम हैं। चुनौती यह है कि इन स्थलों को विश्वस्तरीय सुविधाओं, बेहतर प्रबंधन और सतत पर्यटन के साथ कैसे जोड़ा जाए।

यदि कनेक्टिविटी, सुरक्षा, स्वच्छता, डिजिटल सुविधाओं और स्थानीय भागीदारी का विस्तार इसी गति से होता रहा, तो उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है।

पर्यटन केवल यात्राओं का विषय नहीं है। यह संस्कृति को दुनिया से जोड़ने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार पैदा करने का माध्यम है। उत्तर प्रदेश आज अपनी प्राचीन आध्यात्मिक विरासत और आधुनिक विकास के बीच एक नया संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। अयोध्या से काशी, ब्रज से बुद्धभूमि तक—उत्तर प्रदेश अब केवल भारत की सांस्कृतिक राजधानी नहीं, बल्कि विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई पहचान गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।



## अवसर, चुनौतियां और आगे की राह

# एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2029-30 तक अपनी अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह केवल आर्थिक उपलब्धि का लक्ष्य नहीं है, बल्कि राज्य को देश की विकास यात्रा का प्रमुख इंजन बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा भी है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य के लिए यह लक्ष्य जितना प्रेरक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) लगभग 30.25 लाख करोड़ रुपये के आसपास है। सरकार का अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक यह बढ़कर लगभग 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। इसके बाद 2026-27 से 2029-30 के बीच लगातार तेज आर्थिक विस्तार की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए राज्य को औसतन 24 से 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करनी होगी, जबकि वर्तमान वृद्धि दर लगभग 13 से 14 प्रतिशत के बीच है। यही अतर सरकार के सामने सबसे बड़ी परीक्षा बनकर खड़ा है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं होंगी। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, निवेश, रोजगार, निर्यात, तकनीक और बुनियादी ढांचे में समानांतर गति से विकास सुनिश्चित करना होगा। विकास की रफ्तार तभी बढ़ेगी जब इन सभी क्षेत्रों में समन्वित और दीर्घकालिक रणनीति अपनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसका कृषि क्षेत्र है। राज्य देश के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में शामिल है। अब आवश्यकता केवल उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि कृषि को मूल्य संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, आधुनिक तकनीक और निर्यात से जोड़ने की है। यदि किसानों को बेहतर बाजार, प्रसंस्करण इकाइयों और आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला का लाभ मिलता है तो कृषि राज्य की आर्थिक वृद्धि का मजबूत आधार बन सकती है। विनिर्माण क्षेत्र को भी नई गति देने पर सरकार का विशेष जोर है। विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर, रक्षा औद्योगिक गलियारा, एक्सप्रेस-वे आधारित औद्योगिक विकास, एमएसएमई इकाइयों का विस्तार तथा नए मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टरों की स्थापना से निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि उद्योगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं, कुशल मानव संसाधन और सरल प्रशासनिक व्यवस्था मिलती है तो रोजगार के बड़े अवसर भी सृजित होंगे।

पर्यटन भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, चित्रकूट, कुशीनगर, सारनाथ और आगरा जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के कारण राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बेहतर सड़क, रेल और हवाई संपर्क के साथ पर्यटन अवसंरचना का विस्तार स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इससे होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, खान-पान और अन्य सेवा क्षेत्रों में भी व्यापक रोजगार उत्पन्न होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। डेटा सेंटर, आईटी पार्क, स्टार्टअप इकोसिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को प्रोत्साहन देकर सरकार नए निवेश आकर्षित करना चाहती है। युवाओं की बड़ी आबादी को तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ना इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार वर्ष 2047 के लिए विकसित उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार करा रही है। इसमें छह ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय को लगभग 36 लाख रुपये तक पहुंचाने का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया है। यह दस्तावेज केवल भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने का आधार बनेगा। इसके अल्पकालिक लक्ष्यों से भी एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण सहायता मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के सामने कई चुनौतियां भी हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, निवेश प्रवाह में उतार-चढ़ाव, महंगाई, ऊर्जा लागत और निर्यात बाजार की चुनौतियां राज्य की विकास गति को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा निवेश परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, प्रशासनिक दक्षता, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी भी सफलता के लिए आवश्यक होगी। इसी संदर्भ में राजधानी लखनऊ में आयोजित 'लखनऊ डायलॉग-2026' में भी विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर विस्तार से चर्चा की। गिरि विकास अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि भारत को दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती के लिए संस्थागत क्षमता को और सशक्त बनाना होगा। वहीं संस्थान के निदेशक डॉ. हर्ष शर्मा ने स्पष्ट किया कि विकसित भारत का सपना उत्तर प्रदेश के तीव्र आर्थिक विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है। विशाल जनसंख्या, बढ़ता शहरीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, नए एयरपोर्ट, औद्योगिक निवेश और डिजिटल अवसंरचना राज्य को नई आर्थिक पहचान दे रहे हैं। यदि इन प्रयासों के साथ नीति निर्माण, निवेश और रोजगार सृजन की गति बनी रहती है तो एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य केवल सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि वास्तविक उपलब्धि में भी बदल सकता है।

स्पष्ट है कि यह लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए सरकार, उद्योग जगत, किसानों, उद्यमियों, निवेशकों और समाज के सभी वर्गों को साझा प्रयास करने होंगे। यदि विकास की वर्तमान गति को और अधिक प्रभावी बनाया गया तथा प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और सुधार लगातार जारी रहे, तो उत्तर प्रदेश न केवल देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा।




# उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए यूनिफाइड मॉडल भवन विनियम-2026 तैयार

प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लक्ष्य को और अधिक गति प्रदान करने एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भवन निर्माण और विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यूनिफाइड मॉडल भवन विनियम-2026 तैयार किया गया है। जिसके तथ्यों का आज पिकप भवन में आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी के समक्ष अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में सभी तथ्यों पर विस्तृत चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, गीडा, यूपीसीडा और यूपीडा के लिए बनाए गए यूनिफाइड मॉडल भवन विनियम से मैन्यूफेक्चरिंग, पर्यटन, आईटी, आईटीईएस, लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित यूनिफाइड मॉडल भवन विनियम-2026 को जल्द ही मंत्री परिषद के समक्ष भेजा जाएगा। जिसकी संस्तुति के बाद भवन निर्माण उपविधि को लागू किया जाएगा।

मंत्री नन्दी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने के लिए लगातार नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं। यूनिफाइड मॉडल भवन विनियम-2026 इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो प्रदेश में विकास को नियंत्रित करने के बजाय विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध में



जो भी विसंगतियां या समस्यायें आ रही हों, उन्हें शासन स्तर से दूर किया जाय।

मंत्री नंदी ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य निवेशकों, उद्यमियों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए प्रदेश को देश का अग्रणी औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्र बनाना है। मॉडल भवन विनियम-2026 प्रदेश में निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि नए विनियम उत्तर प्रदेश को आधुनिक, निवेश-अनुकूल और सतत विकास वाले राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायें। इसके लिए नए भवन विनियमों का उद्देश्य भूमि का अधिकतम और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाना तथा निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। इससे उद्योगों की स्थापना तेज होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।



मंत्री नन्दी ने कहा कि वर्तमान समय की औद्योगिक आवश्यकताओं, बढ़ते निवेश और आधुनिक शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए नए मॉडल भवन विनियम तैयार किए जाने से सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भवन निर्माण नियमों में एकरूपता आएगी और प्रक्रियाएं अधिक सरल एवं पारदर्शी होंगी।

बैठक में बताया गया कि मॉडल भवन विनियम-2026 में भूमि के बेहतर उपयोग और ऊर्ध्वाधर विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। नए नियमों के तहत-भू-आच्छादन, सेटबैक और पार्किंग मानकों को तर्कसंगत बनाया गया है। विभिन्न श्रेणियों में एफएआर में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। सड़क की चैड़ाई के आधार पर अनुमेय एफएआर को बढ़ाया गया है। 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर एफएआर की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। इससे सीमित भूमि पर अधिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शहरों के अनियंत्रित विस्तार को नियंत्रित करते हुए आधुनिक एवं सघन विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

बताया गया कि नए विनियमों में भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। प्रमुख प्रावधानों में-100 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंडों तथा 30 वर्गमीटर तक के वाणिज्यिक भूखंडों के लिए 1 पंजीकरण शुल्क पर पंजीकरण एवं स्व-प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गयी है। निर्धारित सीमा तक तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तैयार नक्शों के आधार पर डीम्ड स्वीकृति का प्रावधान है। डीम्ड एनओसी अप्रूवल सिस्टम विकसित करने की पहल, पुराने भवनों में कंपाउंडिंग, एडिशन एवं ऑल्टरेशन पर भी नए नियम लागू होंगे।

मॉडल भवन विनियमों में औद्योगिक उपयोग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें फ्लैटेड फैक्टरी, एमएसएमई इकाइयां, गैर-एमएसएमई उद्योग, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों तथा डाटा सेंटर को शामिल किया गया है। 4 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक भूखंडों पर श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री की सुविधा का प्रावधान किया गया है। डाटा सेंटर के लिए अतिरिक्त एफएआर और पार्किंग मानकों में राहत प्रदान की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में स्टिल्ट एवं पोडियम पार्किंग की अनुमति भी दी गई है।

आवासीय क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग, प्लॉटेड विकास और मल्टी यूनिट आवास के लिए नियमों को सरल बनाया गया है। प्रमुख प्रावधानों में-ग्रुप हाउसिंग के लिए न्यूनतम भूखंड आकार 2000 वर्गमीटर निर्धारित, 300 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर मल्टी यूनिट श्रेणी का प्रावधान, 1500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले ग्रुप हाउसिंग भूखंडों पर पोडियम पार्किंग की अनुमति, प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के किफायती आवास मानकों को शामिल किया गया है।

इस व्यवस्था से वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए-12 मीटर या उससे अधिक चैड़ी सड़कों पर वाणिज्यिक भवनों की अनुमति, 20 कमरों तक के होटलों के लिए न्यूनतम भूखंड आकार की बाध्यता समाप्त, बड़े होटलों के लिए न्यूनतम 500 वर्गमीटर भूखंड निर्धारित, आईटी/आईटीईएस, कार्यालय और सर्विस अपार्टमेंट के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र के लिए भी नियमों को व्यावहारिक बनाया गया है। डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, नर्सिंग होम और अस्पतालों के लिए अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। एम्बुलेंस पार्किंग का प्रावधान किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए नर्सरी से विश्वविद्यालय स्तर तक भूखंड आकार को तर्कसंगत बनाया गया है। स्कूल बस पार्किंग और पिक-अप ड्रॉप-ऑफ जोन की व्यवस्था भी की गई है। बताया गया कि मॉडल भवन विनियम-2026 में मिश्रित उपयोग और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को विशेष महत्व दिया गया है। 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों के किनारे मिश्रित उपयोग विकास को अनुमति दी जाएगी। इससे आवास, वाणिज्यिक गतिविधियों और सेवाओं का संतुलित विकास होगा तथा आधुनिक शहरों के निर्माण को गति मिलेगी। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी विजय किरन आनन्द सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

## वीबी-जी राम जी अधिनियम पर मंथन

# 'पंच सम्मेलन'

**डबल इंजन की सरकार की मंशा है कि ग्राम का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है।**
**उपमुख्यमंत्री**

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य गुरूवार को राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में प्रयागराज में आयोजित 'पंच सम्मेलन' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होते हुए दीप प्रज्ज्वलन व मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त मार्गदर्शिका वीबी जी राम जी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण) से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया। सम्मेलन में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फाफामऊ की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति भी दी गई।

आयोजित सम्मेलन में ग्राम पंचायतों से आए ग्राम प्रधानों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों की क्षमता को सुदृढ़ करते हुए वीबी जी राम जी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर संस्थागत तैयारियों को मजबूत करना है।

आयोजित सम्मेलन में ग्राम प्रधानों को वीबी-जी राम जी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों एवं उद्देश्यों से अवगत कराया गया। साथ ही, ग्राम पंचायतों की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने, विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से सहभागी एवं साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण को बढ़ावा देने, विभिन्न योजनाओं के बेहतर अभिसरण ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही को मजबूत करने तथा अधिनियम के प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर मा0 उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज यहां पर विकसित भारत



गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) की पुस्तिका का विमोचन हुआ है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तिका में कैसे विकसित ग्राम सभा, ग्रामीण क्षेत्र बनाना है, इससे सम्बंधित सभी जानकारियां पुस्तिका में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना का शुभारम्भ 01 जुलाई, 2026 को हुआ था। कहा कि अभी तक इस योजना में जिस अनुपात में काम होना चाहिए था, अभी उतनी श्रमशक्ति हमारे ग्राम सभा के विकास के लिए नहीं लगी है। उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना के अन्तर्गत लीकेज की सम्भावना नहीं है। कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम प्रधानों तथा अन्य सम्बंधित लोगो से जी राम जी योजना के शुरू होने के बाद आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि आप लोग समस्याओं को लिखित रूप में दे सकते है, सभी समस्याओं का शीघ्रता से समाधान सुनिश्चित कराया जायेगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की मंशा है कि ग्राम का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है। मा0 उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब लोगो को अमीर बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत सरोवरों की साफ-सफाई कराये जाने तथा कार्यक्रम का आयोजन कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से अच्छे कामों का सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा है। उन्होंने सरकारी सेवकों को ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कहा है। कहा कि डबल इंजन की सरकार में पात्र लोगो को आवास उपलब्ध हुआ है तथा आगे भी पात्रों को चिन्हित कर आवास योजना से लाभान्वित कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज विकास कार्य के लिए जो धनराशि जारी होती है, उसका शत-प्रतिशत पैसा योजनाओं में उपयोग होता है। भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। डबल इंजन की सरकार में महिलाएं लगातार सशक्त हो रही है तथा आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत तीनों ईकाईयों को मिलकर ग्रामीण क्षेत्र को चमाचम बनाते हुए हर प्रकार से मजबूत बनाना है। प्रदेश सरकार में बिजली व्यवस्था चुस्त-दूरूस्त हुई है तथा निर्धारित समय के अनुसार शहरी तथा गांव क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में देश व प्रदेश में सकारात्मक बदलाव हुआ है। विकास के बड़े-बड़े कार्य हुए है तथा हो रहे है, जो धरातल पर दिखायी दे रहे है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। प्रदेश में रेल उपरगामी, ओवरब्रिज बनने से लोगो को होने वाली परेशानियों से निजात मिली है। अच्छी सड़के, 6 लेन पुल, गंगा एक्सप्रेस वे, रिंग रोड़ के निर्माण से प्रयागराज में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे है। कहा कि जिस प्रकार प्रयागराज बदला है, वैसे ही आपके ग्राम की स्थिति भी बदलनी चाहिए, यह लक्ष्य लेकर आप सभी लोग चले। कहा कि 2047 के पहले सभी ग्राम पंचायतों को विकसित ग्राम पंचायत बनाना है। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ0 प्रभाकर त्रिपाठी ने किया।

कार्यक्रम में बताया गया कि जनपद प्रयागराज में वीबी जी राम जी योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों की संख्या-3034 है, पाँच लाख से अधिक की स्वीकृत परियोजनायों की कुल संख्या-118 है। कुल महिला मेट की संख्या 2742 है जनपद प्रयागराज में वीबी जी राम जी योजनान्तर्गत सृजित मानव दिवस 185701, सृजित मानव दिवस में-महिला-87249 अनुसूचित जाति-85154 कुल सक्रिय श्रमिक- 242660 है।

इस अवसर पर माननीय विधायक फाफामऊ श्री गुरु प्रसाद मौर्य, जिलाध्यक्ष यमुनापार श्री राजेश शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा श्री अवधेश गुप्ता, ब्लॉक प्रमुखगण, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, उपायुक्त उद्योग, जिला विकास अधिकारी श्री जी0पी0 कुशवाहा, परियोजना निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री दिनेश सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रवि शंकर द्विवेदी, समस्त खंड विकास अधिकारी, विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए हुए ग्राम प्रधानगण, माननीय अन्य जनप्रतिनिधिगण के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।



# यूपी बनेगा आधुनिक कौशल एवं रोजगार का हब

योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को आधुनिक कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए आईटीआई की प्रशिक्षण व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने जा रही है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के राजकीय आईटीआई को पारंपरिक प्रशिक्षण केंद्रों तक सीमित न रखते हुए आधुनिक तकनीक, नए ट्रेड और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप भविष्य के कौशल एवं रोजगार केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसी क्रम में बुधवार को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ स्थित प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागीय गतिविधियों का जायजा लेने के साथ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर प्रशिक्षण व्यवस्था, विभागीय योजनाओं की प्रगति तथा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयासों की समीक्षा की। बैठक में प्रदेशभर में संचालित राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रशिक्षकों की उपलब्धता, तकनीकी संसाधनों, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आधुनिक ट्रेडों तथा प्रशिक्षार्थियों को रोजगार से जोड़ने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।

कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि युवाओं के सीखने का तरीका तेजी से बदल रहा है और डिजिटल माध्यमों तथा नई तकनीकों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कौशल प्रशिक्षण को भी आधुनिक, तकनीक आधारित और रोजगारपरक बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिजिटल लर्निंग, आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरतों को प्रशिक्षण व्यवस्था से जोड़ा जाए तथा आईटीआई में उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।





मंत्री अग्रवाल ने कहा कि आईटीआई [illegible] कौशल आधारित करियर विकल्पों की के लिए बेहतर करियर और रोज[illegible] जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए मजबूत माध्यम है। विद्यार्थियों में [illegible] हैं। उन्होंने कहा कि आईटीआई में आधुनिक के प्रति आकर्षण और विश्वास बढ़ाने के लिए और रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देकर प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। स्कूल एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को युवाओं के लिए अधिक कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों को आईटीआई के आकर्षक बनाया जाना चाहिए। मंत्री कपिल आधुनिक ट्रेडों, रोजगार की संभावनाओं और देव अग्रवाल ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल युवाओं को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बनाना है। इसके लिए आईटीआई और उद्योगों के बीच समन्वय को और मजबूत करने तथा इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ प्रशिक्षण में तकनीकी दक्षता के अलावा कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, इंटरव्यू और कार्यस्थल की आवश्यक क्षमताओं को भी शामिल करने पर जोर दिया। मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के आईटीआई को नई तकनीक, आधुनिक ट्रेड और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य के कौशल केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि हुनरमंद युवा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हैं। योगी सरकार का लक्ष्य है कि आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला प्रत्येक युवा अपने कौशल के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार हासिल करे और प्रदेश की आर्थिक प्रगति में सक्रिय भागीदार बने।

# ERCP से YERP तक

- **क्या राजस्थान में पानी की राजनीति का नया दौर शुरू हो गया?**
- **भजनलाल सरकार की जल नीति ने बदली दिशा-प्यासे राजस्थान को पानी, खेतों को सिंचाई और शहरों को नई उम्मीद**



राजस्थान की राजनीति में अगर कोई मुद्दा दशकों से लगातार जनता की जिंदगी से सीधे जुड़ा रहा है, तो वह है-पानी। रेगिस्तान से लेकर दक्षिणी राजस्थान तक पानी की उपलब्धता केवल विकास का विषय नहीं, बल्कि जीवन, खेती, रोजगार और पलायन से जुड़ा सवाल रहा है। राजस्थान के अनेक हिस्सों में हर साल गर्मियों के साथ पानी का संकट गहराता रहा है। किसान सिंचाई के लिए आसमान की ओर देखते रहे और शहरों में पेयजल आपूर्ति एक बड़ी चुनौती बनी रही।

ऐसे में राजस्थान की मौजूदा भजनलाल शर्मा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी-राज्य के जल संकट का स्थायी समाधान तलाशना।

मुख्यमंत्री  के नेतृत्व में सरकार ने जल प्रबंधन को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP को आगे बढ़ाया। बाद में राजस्थान सरकार ने इसे व्यापक स्वरूप देते हुए Modified PKC-ERCP के रूप में आगे बढ़ाया और राज्य में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को एक बड़े जल प्रबंधन दृष्टिकोण से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए।

यही वह बिंदु है जहां राजस्थान की पारंपरिक 'पानी की राजनीति' को विकास और जल-सुरक्षा की राजनीति में बदलने का दावा सामने आता है।

## पानी: राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल

राजस्थान में पानी का संकट नया नहीं है। राज्य का बड़ा हिस्सा शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र में आता है। कई जिलों में भूजल स्तर लगातार चिंता का विषय रहा है। वर्षा का असमान वितरण स्थिति को और चुनौतीपूर्ण बनाता है। पानी की कमी का सीधा प्रभाव खेती पर पड़ता है। किसान के पास जमीन हो लेकिन सिंचाई का भरोसा न हो, तो खेती की उत्पादकता सीमित रहती है। पानी की कमी का असर पशुपालन, उद्योग, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यही कारण है कि राजस्थान में किसी भी सरकार के लिए जल प्रबंधन केवल एक विभागीय विषय नहीं हो सकता। यह सीधे तौर पर राजनीतिक और सामाजिक प्राथमिकता बन जाता है। पिछले वर्षों में राजस्थान में नदियों को जोड़ने, बांधों और नहरों के निर्माण तथा पेयजल योजनाओं को लेकर कई घोषणाएं हुईं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रही-इन योजनाओं को जमीन पर उतारना।

## ERCP: पूर्वी राजस्थान के लिए बड़ी उम्मीद

Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) को पूर्वी राजस्थान के जल संकट के समाधान की दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में देखा गया। इसका उद्देश्य मानसून के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त जल का बेहतर उपयोग करते हुए पूर्वी राजस्थान के जल-वंचित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाना है। ERCP से जुड़े मूल विचार का केंद्र यह था कि बारिश के मौसम में बहकर निकल जाने वाले पानी का अधिकतम उपयोग किया जाए और उसे उन क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए जहां पानी की कमी अधिक है। राजस्थान के लिए इसका महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि पूर्वी राजस्थान के अनेक जिले




कृषि, पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए जल संसाधनों पर दबाव महसूस करते रहे हैं। भजनलाल सरकार ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने को प्राथमिकता दी और केंद्र के सहयोग से Modified PKC-ERCP के रूप में इसे नई दिशा मिली।

## राजस्थान-मध्य प्रदेश समझौता: विवाद से समाधान की ओर

जल परियोजनाओं में सबसे बड़ी चुनौती केवल पैसा या तकनीक नहीं होती। कई बार अंतरराज्यीय सहमति उससे भी बड़ी चुनौती होती है। ERCP को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबे समय से विभिन्न मुद्दे रहे थे। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच समझौता होना परियोजना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। दिसंबर 2024 में संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौते तथा केंद्र सरकार की भूमिका ने परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता खोला। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पानी जैसे संवेदनशील विषय पर दो राज्यों के बीच सहमति बनने का सीधा लाभ परियोजना के क्रियान्वयन को मिल सकता है। यही वह बदलाव है जिसे भजनलाल सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों में गिनाती है-जल विवाद को राजनीतिक बहस से निकालकर परियोजना आधारित समाधान की दिशा में ले जाना।

## YERP: पानी को विकास के बड़े मॉडल से जोड़ने की कोशिश

राजस्थान में जल संकट का समाधान केवल एक परियोजना से संभव नहीं है। इसी सोच के साथ जल संरक्षण, पेयजल, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन को व्यापक रणनीति का हिस्सा बनाया जाना आवश्यक है। इसी व्यापक दृष्टिकोण में YERP-Youth Employment/Enterprise संबंधित पहल जैसे विकासात्मक संदर्भों को भी जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन जल परियोजनाओं के संदर्भ में आधिकारिक नाम और स्वरूप का उल्लेख करते समय सरकारी दस्तावेजों की पुष्टि आवश्यक है। इसलिए राजस्थान की जल नीति की मुख्य धुरी ERCP/Modified PKC-ERCP, जल जीवन मिशन, सिंचाई परियोजनाएं, बांध, नहरें और स्थानीय जल संरक्षण को ही माना जाना अधिक सटीक होगा। पानी का सवाल रोजगार से भी जुड़ा है। जहां सिंचाई पहुंचेगी, वहां कृषि उत्पादन बढ़ेगा। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पशुपालन को मजबूती मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ेगा। अर्थात पानी की एक बूंद का

प्रभाव खेत से बाजार और बाजार से रोजगार तक जाता है।

### किसान के लिए पानी का अर्थ क्या है?

राजस्थान के किसान के लिए पानी केवल सिंचाई की सुविधा नहीं है। यह उसकी फसल की सुरक्षा है। बारिश पर निर्भर किसान के सामने सबसे बड़ी अनिश्चितता मौसम की होती है। यदि किसी क्षेत्र में सिंचाई का भरोसेमंद स्रोत उपलब्ध हो जाए तो किसान बेहतर फसल का चुनाव कर सकता है। वह एक से अधिक फसल लेने की योजना बना सकता है। कृषि उत्पादकता बढ़ सकती है और उसकी आय में भी वृद्धि की संभावना बनती है। ERCP जैसी परियोजनाओं की सबसे बड़ी सफलता इसी कसौटी पर मापी जाएगी कि इससे वास्तव में कितने किसानों को सिंचाई का लाभ मिला और कितने क्षेत्रों की जल उपलब्धता बेहतर हुई। भजनलाल सरकार के लिए यह परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका राजनीतिक लाभ तभी स्थायी होगा जब ग्रामीण राजस्थान इसे अपने खेत और अपने घर तक महसूस करे।

## पेयजल: सबसे सीधा जनसरोकार

- सिंचाई से भी ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है—पीने का पानी।
- ग्रामीण राजस्थान में महिलाओं और परिवारों को लंबे समय तक पानी लाने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती रही है। गर्मियों में यह समस्या और गंभीर हो जाती है।
- जल जीवन मिशन के माध्यम से घर-घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य इसी समस्या का समाधान है। राजस्थान में इस मिशन को गति देना भी राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र रहा है।
- यदि किसी गांव में नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध होता है तो इसका असर सीधे महिलाओं, बच्चों और परिवारों के स्वास्थ्य एवं समय पर पड़ता है।
- इसलिए राजस्थान में जल परियोजनाओं का वास्तविक मूल्यांकन केवल कितने किलोमीटर नहर बनी या कितने करोड़ रुपये खर्च हुए, इससे नहीं होना चाहिए। असली सवाल यह होना चाहिए कि कितने घरों को पानी मिला और कितने खेतों तक सिंचाई पहुंची।
- पारंपरिक जल स्रोतों की वापसी भी जरूरी
- राजस्थान के पास जल संरक्षण की अपनी समृद्ध परंपरा रही है। बावड़ी, तालाब, जोहड़, नाड़ी, टांका और कुंड जैसे पारंपरिक जल स्रोत सदियों से स्थानीय जल प्रबंधन का आधार रहे हैं।
- आधुनिक परियोजनाओं के साथ यदि इन पारंपरिक स्रोतों का पुनर्जीवन भी किया जाए तो राजस्थान की जल सुरक्षा और मजबूत हो सकती है।
- वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण पर जोर देकर स्थानीय स्तर पर पानी को रोकना जरूरी है। बड़े बांध और नहरें राज्य की जल जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन गांव के तालाब और जल स्रोत भी जल सुरक्षा की पहली स्थानीय दीवार हैं।
- भजनलाल सरकार के सामने आने वाले वर्षों में यही अवसर है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ 'हर बूंद को रोकने' की स्थानीय रणनीति को भी मजबूत किया जाए।

## पानी से उद्योग और निवेश तक

राजस्थान में औद्योगिक विकास की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन किसी भी उद्योग के लिए पानी एक आवश्यक संसाधन है। जहां पर्याप्त जल उपलब्धता होगी, वहां उद्योगों के लिए निवेश का वातावरण बेहतर हो सकता है। कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, टेक्सटाइल और अन्य जल-आधारित गतिविधियों को भी स्थिर जल संसाधन से लाभ मिल सकता है। इस लिहाज से जल परियोजनाएं केवल किसान कल्याण की योजनाएं नहीं हैं। वे राजस्थान की औद्योगिक और आर्थिक रणनीति का भी हिस्सा हैं।

## क्या खत्म होगी पानी की राजनीति?

यही सबसे बड़ा सवाल है। राजस्थान में पानी लंबे समय से चुनावी मुद्दा रहा है। हर सरकार ने जल संकट के समाधान के लिए योजनाएं बनाईं और विपक्ष ने उनकी गति तथा क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। लेकिन अगर ERCP और उससे जुड़ी परियोजनाएं वास्तविक रूप से जमीन पर उतरती हैं, सिंचाई क्षेत्र बढ़ता है, पेयजल की उपलब्धता सुधरती है और ग्रामीण राजस्थान की जल समस्या कम होती है, तो पानी की राजनीति का स्वरूप बदल सकता है। तब बहस यह नहीं होगी कि 'पानी कौन लाएगा?', बल्कि यह होगी कि 'पानी का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए?' यही किसी भी जल नीति की सबसे बड़ी सफलता होगी।

## भजनलाल सरकार के सामने अवसर और चुनौती

भजनलाल सरकार के लिए जल क्षेत्र में सबसे बड़ा अवसर यह है कि वह राजस्थान के विकास को जल-सुरक्षा से जोड़ सकती है।

लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। बड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, लागत को नियंत्रित रखना, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, जल वितरण में क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करना और परियोजनाओं के लाभ को अंतिम किसान और अंतिम घर तक पहुंचाना जरूरी होगा।

इसके साथ ही भूजल का अत्यधिक दोहन रोकना और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना भी आवश्यक है।

सरकार की सफलता का असली पैमाना यही होगा कि परियोजनाओं की घोषणा और शिलान्यास से आगे बढ़कर पानी वास्तव में खेत और घर तक पहुंचे।

## पानी की राजनीति से जल-सुरक्षा की राजनीति तक

राजस्थान की कहानी में पानी हमेशा से सबसे बड़ा सवाल रहा है। यह सवाल किसान का है, महिला का है, गांव का है, शहर का है और उद्योग का भी है। ERCP और Modified PKC-ERCP जैसी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में भजनलाल सरकार ने जिस तरह अंतरराज्यीय सहमति और केंद्र के सहयोग को परियोजना के साथ जोड़ा है, वह राजस्थान के जल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अब जरूरत है कि बड़े जल प्रोजेक्ट्स के साथ छोटे तालाब, पारंपरिक जल स्रोत, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को भी समान प्राथमिकता मिले। अगर राजस्थान में आने वाले वर्षों में नदियों और नहरों का पानी खेतों तक, पाइपलाइन का पानी घरों तक और बारिश का पानी जमीन के भीतर तक पहुंचाने की एकीकृत व्यवस्था सफल होती है, तो यह केवल एक सरकारी योजना की सफलता नहीं होगी। यह राजस्थान की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। क्योंकि जिस प्रदेश में कभी पानी चुनावी वादा था, वहां यदि पानी जीवन की स्थायी सुविधा बन जाए—तो यही असली सुशासन की पहचान होगी। भजनलाल सरकार के लिए जल क्षेत्र की सबसे बड़ी परीक्षा भी यही है और सबसे बड़ा अवसर भी—राजस्थान को 'पानी की कमी वाले राज्य' की पहचान से निकालकर 'जल-सुरक्षित राजस्थान' की ओर ले जाना।



स्टार्टअप से स्पेस टेक्नोलॉजी तक नई उड़ान

# योगी सरकार में यूपी के युवा बना रहे 'रॉकेट

## AI, इनोवेशन और नई तकनीक के सहारे आत्मनिर्भर बन रहा उत्तर प्रदेश—मोदी सरकार के सहयोग से युवाओं के सपनों को मिला स्टार्टअप इकोसिस्टम

उत्तर प्रदेश को लंबे समय तक देश के सबसे बड़े युवा आबादी वाले राज्यों में गिना जाता रहा है, लेकिन आज यही युवा आबादी प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिक और तकनीकी ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हाथ में डिग्री और नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं की तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है। अब उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी मांगने के साथ-साथ नौकरी देने वाला उद्यमी बनने का सपना भी देख रहा है।

- स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, एग्रीटेक और यहां तक कि स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के युवाओं की बढ़ती भागीदारी इस बदलाव का संकेत है।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत और संस्थागत ढांचा तैयार करने पर जोर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की Startup India, Digital India, Make in India, Skill India और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों ने राज्य के युवाओं के लिए व्यापक अवसरों का वातावरण तैयार किया है।
- यानी केंद्र की नीतियां और प्रदेश की योजनाएं मिलकर उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्थानीय बाजार से राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का रास्ता तैयार कर रही हैं।

## नौकरी खोजने से नौकरी देने तक

उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले सोच में आए बदलाव को समझना होगा। एक समय युवा का लक्ष्य सरकारी नौकरी या किसी बड़ी कंपनी में रोजगार हासिल करना माना जाता था। आज परिस्थितियां बदल रही हैं। कॉलेज से निकलने वाला युवा अपने आइडिया को बिजनेस मॉडल में बदलने, डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने और अपनी कंपनी खड़ी करने के बारे में सोच रहा है। उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति ने इसी मानसिकता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। शुरुआती चरण के उद्यमियों के लिए प्रोटोटाइप तैयार करने, सीड फंडिंग, मेंटरशिप, इनक्यूबेशन और पेटेंट जैसी जरूरतों को नीति समर्थन से जोड़ने की कोशिश की गई है। इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत केवल एक विचार से होती है। विचार को उत्पाद में बदलने के लिए पूंजी, तकनीक, मार्गदर्शन और बाजार की आवश्यकता होती है। यदि सरकार शुरुआती चरण में इन जरूरतों को पूरा करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराती है, तो युवाओं के जोखिम लेने का आत्मविश्वास बढ़ता है।

## AI: नई अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा अवसर

- आज दुनिया जिस तकनीकी बदलाव से गुजर रही है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है।
- AI अब केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट, ई-कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और प्रशासन तक में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है।
- उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए AI इसलिए बड़ा अवसर है क्योंकि इसके लिए केवल बड़े शहर में फैक्ट्री लगाना जरूरी नहीं। एक युवा लैपटॉप और इंटरनेट के माध्यम से AI आधारित समाधान तैयार कर सकता है और उसे दुनिया के किसी भी बाजार तक पहुंचा सकता है।
- AI आधारित स्टार्टअप कृषि में फसल संबंधी सलाह दे सकते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में डेटा विश्लेषण में सहायता कर सकते हैं, शिक्षा में व्यक्तिगत लर्निंग समाधान विकसित कर सकते हैं और छोटे कारोबारियों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं।
- यानी AI उत्तर प्रदेश के युवा को केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि तकनीक का निर्माता बनने का अवसर दे रहा है।

## स्टार्टअप से स्पेस तक—बदल रही सोच

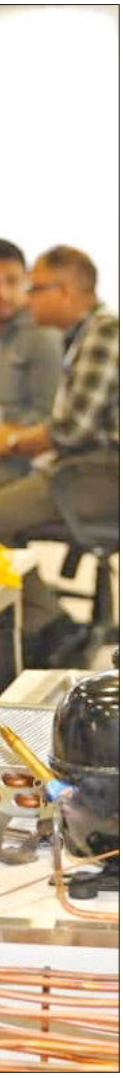
सबसे दिलचस्प बदलाव उन क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है जिन्हें कभी केवल बड़ी सरकारी संस्थाओं या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्षेत्र माना जाता था।



स्पेस टेक्नोलॉजी इसका बड़ा उदाहरण है। भारत में निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खुलने और IN-SPACe जैसे संस्थागत ढांचे के विकास ने युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। रॉकेट, सैटेलाइट, लॉन्च सिस्टम, स्पेस डेटा, रिमोट सेंसिंग और पृथ्वी अवलोकन जैसी तकनीकों में निजी कंपनियां और स्टार्टअप काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए यह एक नई दुनिया है। आज इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाला युवा केवल सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करने की कल्पना नहीं करता। वह ड्रोन, सैटेलाइट, रोबोटिक्स और स्पेस सिस्टम विकसित करने का सपना देख सकता है। यही बदलाव भारत के आत्मनिर्भरता अभियान की वास्तविक ताकत है।

## मोदी सरकार का साथ, योगी सरकार की जमीन

उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का तालमेल महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की Startup India, Digital India, Make in India, Skill India और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों ने देश में उद्यमिता के लिए व्यापक वातावरण बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की जरूरतों के अनुरूप स्टार्टअप नीति, इनक्यूबेशन सेंटर, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को जोड़ने तथा स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा



देने पर जोर दिया। यह मॉडल महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी युवा को केवल नीति की घोषणा नहीं चाहिए। उसे अपने शहर में इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, प्रशिक्षण, निवेशक और बाजार तक पहुंच चाहिए। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ने की कोशिश इसी दिशा में महत्वपूर्ण है।

## यूपी के छोटे शहरों से निकल रहे बड़े आइडिया

स्टार्टअप क्रांति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब नवाचार केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे महानगरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। लखनऊ, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, आगरा और अन्य शहरों में भी युवा टेक्नोलॉजी और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।

## यह बदलाव उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

यदि स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप विकसित होते हैं तो युवा को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता कम हो सकती है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर नए रोजगार पैदा होते हैं। एक सफल स्टार्टअप केवल अपने संस्थापक को रोजगार नहीं देता। उसके साथ डेवलपर, डिजाइनर, मार्केटिंग प्रोफेशनल, अकाउंटेंट, सेल्स टीम और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए भी अवसर पैदा होते हैं।

## ड्रोन और एग्रीटेक: गांव तक पहुंचती नई तकनीक

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए तकनीकी विकास का वास्तविक लाभ तभी माना जाएगा जब वह गांव और किसान तक पहुंचे। ड्रोन तकनीक कृषि क्षेत्र में तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। फसल निगरानी, कीटनाशक और उर्वरक के छिड़काव, भूमि सर्वेक्षण और डेटा आधारित कृषि प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग बढ़ सकता है। युवा उद्यमी इस क्षेत्र में सेवा आधारित कारोबार विकसित कर सकते हैं। इसी प्रकार एग्रीटेक स्टार्टअप किसानों को मौसम, बाजार, फसल प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित डिजिटल समाधान उपलब्ध करा सकते हैं। यहां स्टार्टअप और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा एक-दूसरे से जुड़ती दिखाई देती है-स्थानीय समस्या का स्थानीय युवा तकनीकी समाधान तैयार करता है और फिर उसे बड़े बाजार तक ले जाता है।

## स्किल डेवलपमेंट: आइडिया के साथ हुनर भी जरूरी

स्टार्टअप तभी सफल होगा जब उसके पीछे कुशल मानव संसाधन होगा। इसलिए युवाओं को केवल डिग्री नहीं, बल्कि स्किल देना भी जरूरी है। कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, AI, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास आने वाले वर्षों में रोजगार की दिशा तय कर सकता है। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यदि तकनीकी संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल बनता है तो युवाओं को पढ़ाई के साथ वास्तविक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण मिल सकता है। यही वह क्षेत्र है जहां उत्तर प्रदेश की विशाल युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।

## महिलाएं भी बन रही हैं टेक उद्यमिता का हिस्सा

नई अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू महिला उद्यमिता है। स्टार्टअप और डिजिटल बिजनेस में महिलाओं के लिए प्रवेश की बाधाएं पारंपरिक उद्योगों की तुलना में कई मामलों में कम हो सकती हैं। घर से डिजिटल कारोबार शुरू करने से लेकर टेक कंपनी बनाने तक महिलाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को डिजिटल तकनीक से जोड़ने पर बड़ा प्रभाव पैदा किया जा सकता है। भविष्य का उत्तर प्रदेश वह हो सकता है जहां महिला समूह स्थानीय उत्पाद बनाएं और युवा टेक उद्यमी उनके लिए ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार करें।

## आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का अगला चरण

उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का अर्थ केवल बाहर से निवेश लाना नहीं है। आत्मनिर्भरता का वास्तविक अर्थ है—प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत बनाना। यदि कोई युवा उत्तर प्रदेश में कंपनी शुरू करता है, स्थानीय लोगों को रोजगार देता है, स्थानीय समस्या का समाधान करता है और देश-विदेश में अपना बाजार बनाता है तो वह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का वास्तविक प्रतिनिधि है। यही कारण है कि स्टार्टअप और इनोवेशन को केवल तकनीकी विषय मानना सही नहीं होगा। यह आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है।

## चुनौतियां अभी बाकी हैं

हालांकि तस्वीर उत्साहजनक है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हर स्टार्टअप सफल नहीं होता। शुरुआती पूंजी, बाजार तक पहुंच, अनुभवी मेंटर, उच्च स्तरीय तकनीकी प्रतिभा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां सामने रहती हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकारी सहायता के साथ निजी निवेश और उद्योग की भागीदारी भी बढ़े। विश्वविद्यालयों में रिसर्च और पेटेंट को बढ़ावा मिले। छोटे शहरों में इनक्यूबेशन सुविधाएं मजबूत हों और युवाओं को असफल होने के बाद दोबारा प्रयास करने का अवसर मिले। स्टार्टअप संस्कृति का अर्थ केवल यूनिकॉर्न बनाना नहीं है। हजारों छोटे लेकिन टिकाऊ उद्यम भी अर्थव्यवस्था के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

## निष्कर्ष: यूपी का युवा अब सिर्फ सपने नहीं देख रहा, उन्हें लॉन्च कर रहा है

- उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति आज परिवर्तन के केंद्र में है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार स्टार्टअप, निवेश, कौशल और औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की व्यापक सोच ने युवाओं को नए क्षेत्रों में प्रवेश करने का आत्मविश्वास दिया है।
- आज का युवा केवल नौकरी की तलाश में नहीं है। वह ऐप बना रहा है, AI मॉडल तैयार कर रहा है, ड्रोन विकसित कर रहा है, कृषि की समस्या का तकनीकी समाधान खोज रहा है, रोबोटिक्स पर काम कर रहा है और अंतरिक्ष तकनीक में कदम रखने का सपना देख रहा है।

## यही नए उत्तर प्रदेश की पहचान है।

- कल तक जिस युवा के लिए रॉकेट केवल आसमान में दिखाई देने वाली चीज थी, आज वही युवा उसके डिजाइन, सॉफ्टवेयर, सेंसर, डेटा और लॉन्च सिस्टम पर काम करने की कल्पना कर रहा है।
- यह बदलाव केवल तकनीक का बदलाव नहीं है। यह सोच का बदलाव है।
- स्टार्टअप से स्पेस तक, गांव के इनोवेशन से ग्लोबल मार्केट तक—उत्तर प्रदेश का युवा अब केवल भविष्य का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि अपने हाथों से भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहा है।
- और यही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है।

# राजनीति की नई परिभाषा लिखते GEN-Z

की बोर्ड की खटखट से शुरू होकर सत्ता के गलियारों को हिला देने वाले युवा आंदोलनों ने पूरी दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल दिया है। लेकिन जहां दुनिया भर में जनरेशन जेड या कहें नई पीढ़ी या संक्षेप में 'जेन जी' की क्रांतियां अक्सर खूनी संघर्षों, तख्तापलट और राजनीतिक अस्थिरता में तब्दील हुयीं, वहीं भारत के युवाओं ने सत्ता को घुटनों पर लाने का एक ऐसा अहिंसक, सटीक और आक्रामक मॉडल तैयार किया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है।

## डिजिटल पीढ़ी की अनूठी क्रांति

हाल के वर्षों में ढाका से लेकर नैरोबी और काठमांडू से लेकर कोलंबो तक जेन जी यानी डिजिटल पीढ़ी ने सड़कों पर उतरकर यह साबित किया है कि वह अब व्यवस्था के मूकदर्शक नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन आंदोलनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिकटोक, इंस्टाग्राम, एक्स या टेलीग्राम आदि की महती भूमिका रही। इनके जरिए तेजी से संगठित होकर विकेंद्रीकृत नेटवर्क बनाए गए। इस प्रक्रिया को एक नया 'डिजिटल सिविल रेजिस्टेंस' मॉडल कहा जा सकता है।

## अन्य देशों के उदाहरण

नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में जब युवाओं का गुस्सा भड़का तो उन्होंने सीधे राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की और सरकारों को उखाड़ फेंका। लेकिन इस उपक्रम में ढाका की सड़कों पर 1000 से अधिक जानें चली गई और पीछे छूट गया एक गहरा राजनीतिक शून्य। कर वृद्धि और भ्रष्टाचार के खिलाफ अफ्रीका में भड़के जेन जी आंदोलन को भी भारी हिंसक दमन का सामना करना पड़ा। यह आंदोलन आक्रामक थे। तात्कालिक रूप से सफल भी हुए, लेकिन अक्सर नीतिगत बदलाव हासिल करने के बजाय व्यवस्थागत अराजकता में बदल गए। नेपाल में 2025-26 में सोशल मीडिया प्रतिबंध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ जेन जी का आंदोलन तेजी से राष्ट्रीय जन आंदोलन बन गया। व्यापक विरोध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और 2026 के चुनाव में युवा समर्थित पार्टी और नेतृत्व को बड़ा जनादेश मिला। केन्या में वित्त विधेयक के खिलाफ आधारित युवा संगठन ने संसद के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया और अंतत सरकार ने विधेयक वापस ले लिया। यह एक स्पष्ट नीतिगत जीत है, हालांकि व्यवस्था के सुधार की मांगे पूरी नहीं हो पाईं। सर्बिया में 'नावी' सब रेलवे स्टेशन हादसे, जिसमें 15 मौतें हुई थी, के बाद छात्रों ने भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन शुरू किया जो राष्ट्रीय स्तर तक फैल गया। वहाँ प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा इनके अलावा इंडोनेशिया, फिलिपींस, पेरु, मोरक्को और मेडागास्कर जैसे देशों में युवा आंदोलन के परिणाम अनिश्चित रहे। कुछ जगह नीति वापसी, सुधार की घोषणाएं हुई, कुछ जगह अंतरिम सरकार बनी और कई मामलों में सरकार गिराया जाना आसान रहा मगर बेहतर शासन खड़ा कर पाना बेहद कठिन साबित हुआ।

## भारत के युवाओं का आंदोलन

भारत में हाल ही में शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर दिखा युवा आंदोलन वैश्विक परिदृश्य से बिल्कुल अलग और अधिक प्रभावी नजर आया। सड़कों पर लाखों की भीड़ पर पुलिस का बल प्रयोग भी हुआ लेकिन जवाब में हिंसा नहीं बल्कि एक अभूतपूर्व संयम और रणनीति थी। जहां दुनिया भर में जेन जी सरकार गिराने में उलझा रहा वहीं भारत के युवाओं ने मुद्दे पर केंद्रित राजनीति को चुना। परिणाम, दशकों बाद किसी जन दबाव के कारण केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और विद्यार्थियों की न्याय संगत मांगों को तुरंत स्वीकार किया गया।

## युवाओं की वैश्विक समझ

दुनिया ने हाल के वर्षों में कभी 'अरब स्प्रिंग' देखा था तो कभी 'ब्लैक लाइव्स मैटर'। आज भारत का युवा इन्हीं आंदोलनों से उपजी वैश्विक चेतना से लैस होकर देश की सड़कों और डिजिटल गलियारों



में लड़ रहा है। वर्तमान आंदोलन की सफलता को इन तीन पैमानों पर समझा जा सकता है

1. इस पीढ़ी ने राजनीति के पारंपरिक तरीके को खारिज कर दिया। इनका कोई एक आका नहीं है, कोई एक चेहरा नहीं है। यह एक विकेंद्रीकृत और स्वतंत्र आंदोलन है जहां हर युवक खुद में एक नेता है।
2. यह पीढ़ी कुएं का मेंढक नहीं है। इंटरनेट के जरिए दुनिया को देख रही इस आबादी को वैश्विक मानक चाहिए। इन्हें घिसी पिटी शिक्षा नहीं बल्कि एआई, रोबोटिक और क्लाइमेट सुधार वाली बातें करनी है। उन्होंने सरकार को मजबूर किया है कि वह पुराने ढर्रे से बाहर आए।
3. जाति, धर्म और संप्रदाय की जिन दीवारों पर पार्टियां सालों से रोटियां सकती आई है जेन जी ने उन दीवारों को ढहा दिया है। नीट घोटाला हो या पर्यावरण का विनाश यह पीढ़ी एक होकर लड़ रही है। इसकी समझ समावेशी और वैश्विक है।

## पेपर लीक के बहाने संस्थागत भ्रष्टाचार से युवाओं की लड़ाई

साल दर साल नीट, नेट, एसएससी और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के पेपर का लीक होना कोई हादसा नहीं बल्कि एक संस्थागत भ्रष्टाचार बन चुका है। युवा सालों तक कमरों में बंद रहकर अपनी जवानी खपा देते हैं और अंत में उन्हें मिलता है एक लीक हुआ प्रश्न पत्र और लाठियां। सरकार एक ऐसी पारदर्शी परीक्षा प्रणाली नहीं दे पाई है जो कि 'लीक प्रूफ' हो। यह प्रशासनिक विफलता की पराकाष्ठा है।

डिग्रियां बांटने वाली फैक्ट्रियां तो खोल दी गई लेकिन जब बात रोजगार की आती है तो सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं होता। आज भारत का उच्च शिक्षित युवा जोमैटो, स्विग्गी या रैपीडो का राइडर बनने पर मजबूर है। 'गिग इकोनॉमी' के नाम पर युवाओं का यह आधुनिक शोषण सरकार की आर्थिक नीतियों के खोखलेपन को उजागर करता है युवाओं का भविष्य असुरक्षित है और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के अधर में भी लटका हुआ है।




## सरकारी सेंसरशिप बर्दाश्त नहीं

दुखद यह है कि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र संवाद से चलते हैं लेकिन कई देशों की तरह यहां भी लोकतंत्र को मूक–तंत्र बनाने की कोशिश की जा रही है। जब भी युवा शांतिपूर्ण ढंग से नौकरियां या परीक्षा सुधारो के लिए आवाज उठाते हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं और कहीं-कहीं तो इंटरनेट भी बंद कर दिया जाता है। डिजिटल स्पेस पर सरकार की यह सेंसरशिप उसकी असुरक्षा और तानाशाही सोच को दर्शाती है जिसका यह नई पीढ़ी अब विरोध करने पर उतर आई है।

## इंटरनेट मीम्स बने हथियार

भारतीय जेन जी की सबसे बड़ी ताकत उनका डिजिटल नेविगेशन रहा। जब तंत्र ने उन्हें दबाना चाहा तो उन्होंने लाठियों का जवाब पत्थरों से नहीं बल्कि डार्क ह्यूमर, व्यंग्य, गालियों और इंटरनेट मीम्स से दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने सत्ता की अकड़ को हास्य का विषय बना दिया। मुख्य धारा की मीडिया जो अब पूर्णतः सरकार परस्त हो गई है, उसको गोदी मीडिया कह कर बहिष्कार कर दिया गया। स्वतंत्र पत्रकारों और जबरदस्त क्रिएटिव रील के जरिए अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाना यह एक ऐसा हथियार था जिसका कोई 'एंटीडोट' सत्ता के पास नहीं था। खास बात यह है कि भारतीय जेन जी आंदोलन ने खुद को केवल इंटरनेट 'एक्टिविज्म' तक सीमित नहीं रखा है बल्कि इसे धरातल पर बदलाव का माध्यम बनाया है। भारतीय युवाओं ने सोशल मीडिया को जन आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना दिया। भारत के युवाओं ने स्थानीय मुद्दों जैसे परीक्षा घोटाले, भाई भतीजा वाद, तंत्र के नकारेपन के साथ पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता आदि को भी वैश्विक स्तर पर ट्रेंड कराया।

## जवाबदेही की दरकार

भले ही उनकी भाषा और शैली अलग हो, भारतीय युवा जाति, धर्म और क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर लैंगिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य और मानवाधिकार जैसे वैश्विक मूल्यों पर अब खुलकर बात कर रहा है। जलवायु परिवर्तन से लेकर शिक्षा नीति पर युवा अब सरकार से खोखले वादों के बजाय डाटा आधारित ठोस जवाबदेही मांग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और अर्थशास्त्री अब चेतावनी दे रहे हैं कि भारत अपने सबसे बड़े अवसर को खो रहा है। जो युवा देश को सुपर पावर बना सकते थे सरकार की असफलता के कारण उनमें ब्रेन–ड्रेन दोबारा तेजी से शुरू हो गया है। देश के भीतर बच्चों में व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश और निराशा है। वैश्विक दृष्टिकोण से एक ऐसा देश जो अपनी युवा ऊर्जा को संभाल नहीं सकता वह कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। वैश्विक थिंक टैंक भी अब यह मान रहे हैं कि भारतीय युवाओं का असंतोष किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं है बल्कि यह उनकी बुनियादी जरूरत और आत्म सम्मान की लड़ाई है।

## छात्र आंदोलन से व्यवस्था परिवर्तन तक

जेन जी ने 21वीं सदी की राजनीति को फिर से परिभाषित किया है। अब परिवर्तन की प्रयोगशाला केवल संसद नहीं बल्कि कैंपस, मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया नेटवर्क भी है। भारतीय जेन जी आंदोलन ने यह भी साफ कर दिया है कि वह सतही राष्ट्रवाद और खोखले वादों की अफीम चाट कर सोने वाले नहीं है। उनकी सफलता इस बात में है कि उन्होंने सरकार को आइना दिखा दिया है। सरकारों की असफलता यह है कि वह इस पीढ़ी को देश की ताकत बनाने के बजाय उन्हें अपना दुश्मन समझने लगती हैं।

# हल्दी में सीसा: स्वाद, सेहत और सुरक्षा का सवाल

सीसा एक अत्यंत विषैला भारी धातु है, जिसका शरीर में कोई सुरक्षित स्तर नहीं माना जाता। विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए इसका प्रभाव अत्यंत हानिकारक हो सकता है। सीसा के लगातार संपर्क से बच्चों की बौद्धिक क्षमता (IQ) में कमी, सीखने में कठिनाई, व्यवहार संबंधी समस्याएँ, एनीमिया और मस्तिष्क के विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। वहीं वयस्कों में यह उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी, हृदय संबंधी समस्याएँ तथा प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बाजार में बिकने वाली हल्दी में अत्यधिक मात्रा में सीसा पाए जाने की कई वैज्ञानिक रिपोर्टें सामने आई हैं। कई मामलों में इसका कारण लेड क्रोमेट (Lead Chromate) नामक पीले रंग के रसायन की मिलावट पाया गया, जिसे हल्दी का रंग अधिक चमकीला दिखाने और उसकी बाजार कीमत बढ़ाने के लिए अवैध रूप से मिलाया जाता है। यह खाद्य मिलावट का एक गंभीर उदाहरण है, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसी संदर्भ में टॉक्सिक्स लिंक द्वारा किए गए एक अध्ययन ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया—क्या हल्दी में सीसा खेत में ही आता है या बाद की प्रक्रिया में मिलाया जाता है? अध्ययन के अंतर्गत छह राज्यों से किसानों के खेतों से सीधे 13 कच्ची हल्दी के नमूने एकत्र कर NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में उनकी जाँच कराई गई। अध्ययन के परिणाम उत्साहजनक रहे। सभी नमूनों में सीसा की मात्रा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI ) द्वारा निर्धारित 10 mg/kg की सीमा से काफी कम पाई गई। अधिकांश नमूनों में सीसा का स्तर 0.5 mg/kg से भी कम था तथा केवल एक नमूने में 1.87 mg/kg दर्ज किया गया। इससे संकेत मिलता है कि खेतों में उगाई गई कच्ची हल्दी सामान्यतः सुरक्षित है और मिट्टी या सिंचाई जल से होने वाला प्रदूषण इस अध्ययन में प्रमुख कारण के रूप में सामने नहीं आया। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि यदि बाजार में बिकने वाली हल्दी में अधिक मात्रा में सीसा पाया जाता है, तो उसका स्रोत संभवतः कटाई के बाद की प्रक्रियाएँ-जैसे प्रसंस्करण, पॉलिशिंग, पैकेजिंग या जानबूझकर की गई मिलावट-हो सकती हैं। इसलिए आवश्यकता है कि केवल खेतों पर नहीं, बल्कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी की जाए। यदि यह निष्कर्ष व्यापक स्तर पर और अधिक अध्ययनों से पुष्ट होते हैं, तो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश होगा। निगरानी का केंद्र केवल खेती तक सीमित न रहकर पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर होना चाहिए। प्रसंस्करण इकाइयों का नियमित निरीक्षण, बाजार में उपलब्ध हल्दी और अन्य मसालों का समय-समय पर परीक्षण, आधुनिक ट्रेसबिलिटी प्रणाली का विकास तथा मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आवश्यक है। साथ ही किसानों, व्यापारियों, प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातकों को भी इस समस्या के स्वास्थ्य और आर्थिक दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना होगा। उपभोक्ता भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित स्रोतों से हल्दी खरीदें, अत्यधिक चमकीले रंग वाली संदिग्ध या असामान्य रूप से सस्ती हल्दी से बचें तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाएँ। सुरक्षित भोजन केवल सरकारी नियमों से नहीं, बल्कि जागरूक उपभोक्ताओं और जिम्मेदार उद्योग से भी सुनिश्चित होता है। भारत विश्व के सबसे बड़े हल्दी उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक है। इसलिए हल्दी की गुणवत्ता केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं, बल्कि किसानों की आजीविका, उपभोक्ताओं के विश्वास और भारतीय मसालों की वैश्विक प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई है। विज्ञान, प्रभावी नियमन और सामाजिक जागरूकता के संयुक्त प्रयासों से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हमारी थाली तक पहुँचने वाली हल्दी वास्तव में स्वास्थ्य का प्रतीक बनी रहे, न कि किसी अदृश्य विषैले खतरे का माध्यम।



# CELEBRATING 73 YEARS OF EXCELLENCE!

# SGRRU

## SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY

### DEHRADUN, UTTARAKHAND

UNLOCKING 2X BENEFITS

**UPTO**

**30% SCHOLARSHIP ON TOTAL COURSE FEE**

**+**

**ADDITIONAL UPTO 100% SCHOLARSHIPS**

ON ELIGIBILITY BASIS

**HURRY! SECURE YOUR SEAT NOW**

FOR MORE DETAILS CALL

7248889111 | 7248889222 | 7248889112 | 7248889113

VISIT OUR WEBSITE

https://www.sgrru.ac.in

TO REGISTER CLICK

https://admissions.sgrru.ac.in/

# राहत टैक्स से फ्रीडम इंटरेस्ट से

## नागरिकों के लिए सुनहरा मौका




**अवधि**
**15 अगस्त से 15 दिसंबर, 2026 तक**

नगर निकायों में लंबित संपत्ति कर
(गृहकर/जलकर/सीवर-कर) हेतु

**एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.)**

पूरा बकाया भुगतान करने पर ब्याज एवं सरचार्ज में मिलेगी
**100% छूट**

**ऑनलाइन तथा ऑफलाइन**
दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा

बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए
अधिकतम **3 किस्तों** की सुविधा

बकाया राशि का **1/3 हिस्सा** 30 दिनों में और शेष **2/3 हिस्सा**
**दो मासिक किस्तों** में जमा करने की सुविधा

1 अप्रैल, 2026 तक लंबित सभी प्रकार की
संपत्तियों के कर पर मिलेगा **OTS का लाभ**



**OTS अपनाएं ब्याज में पूरी राहत पाएं**

अपने नगर निकाय के कार्यालय आएं,
समय रहते OTS का लाभ उठाएं,
कर के बोझ से मुक्ति पाएं.

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

**नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश**
nagarvikas_up UPNagarVikasVibhag NagarVikas_UP @NagarVikasVibhagUP

**टोल फ्री नं. : 1533**